घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 103- गुरूवार 12- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पेट्रोल बंगाल में दिल्ली से 10 ज्यादा महंगा : सीतारमण

टीएमसी को बंगाल की चिंता तो स्टेट जीएसटी हटाएं,इनके लोग कट ले रहे...

नई दिल्ली,11 फरवरी 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के जीएसटी को लेकर आरोपों पर सीतारमण ने कहा, अभिषेक बनर्जी की स्पीच पर मुझे दुख हुआ। उन्होंने जनकारी तोड़ मरोड़कर पेश की। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मरने तक लोग जीएसटी दे रहे हैं। कहां से ला रहे हैं ये बातें। दूध के ऊपर कब जीएसटी लगा,पढ़ाई पर कब लगा। इस पर पीछे बैठे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वहां कट मनी लगती है,इसे फिर सीतारमण ने दोहराया। सीतारमण ने कहा- आप बंगाल में स्टेट जीएसटी हटा सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे। पैसा भी चाहते हैं और बदनाम भी कर रहे हैं। आप अगर बंगाल में लोगों पर बोझ कम करना चाहते हैं तो वहां पेट्रोल के दाम दिल्ली से 10 रुपए ज्यादा है, उसे कम कर दीजिए।

निर्मला सीतारमण बोलीं...कांग्रेस के लोगों को मेरा जवाब सुनने की क्षमता रखनी चाहिए

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को मेरा जवाब सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। ये कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। मैं बताती हूं कि भारत को किसने बेचा। इसे कांग्रेस ने बेचा। बाली में जाकर सौदा करके आए थे। ट्रेड फेलिसिटेशन पर साइन करके आ गए थे। और भारत के फायदे के लिए उसमें कुछ नहीं थी। किसानों के हक से समझौता करने वाली कांग्रेस है। मोदी ने 2014 में डब्ल्यूटीओ में जाकर इसे सुधारा। ये गरीबों को राशन दे नहीं पा रहे थे और ये मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। इनको इसका कोई अधिकार नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप गलत। डेटा को लेकर उनको जानकारी नहीं है। इनको बजट सही से पढ़ के आना चाहिए। ये यहां आकर गलत डेटा देते हैं। महंगाई पूरी तरह कंट्रोल है।

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देगी भाजपा : रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित एपस्टीन फाइल्स को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा में राहुल बिना किसी तर्क,सबूत या पूर्व सूचना के आरोप लगा रहे हैं। इसलिए भाजपा संसदीय दल आज लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देगा। रिजिजू ने बुधवार को संसद परिसर में पत्रकार वार्ता में कहा... कि राहुल के पूरे भाषण में जो भी गलत बातें कही गई हैं,उन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए। साथ ही जिन शब्दों का प्रयोग असंसदीय है और जो झूठे आरोप लगाए गए हैं,उन्हें भी कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए। देश को बेच देने वाले राहुल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में रिजिजू ने कहा... कि इस देश को न कोई बेच सकता है और न ही कोई खरीद सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। रिजिजू ने कहा... कि राहुल गांधी ने बिना पूर्व सूचना दिए मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। हम अध्यक्ष को आवश्यक सूचना देंगे। उन्होंने कहा... कि राहुल जानबूझकर बार-बार ऐसा करते हैं। उनका भाषण आमतौर पर झूठ और आरोपों से भरा होता है। वे भाग जाते हैं और मंत्री का जवाब सुनने के लिए कभी नहीं बैठते।

बजट विकसित भारत की ओर ले जाने वाला दस्तावेज : अनुराग ठाकुर

लोकसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने जहां एक ओर सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया, वहीं विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखे हमले भी किए। उन्होंने कहा कि यह बजट 'विकास एक्सप्रेस' को 'विकसित भारत' की ओर ले जाने वाला दस्तावेज है और यह केवल वित्तीय विवरण नहीं बल्कि समावेशी विकास, वित्तीय अनुशासन और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का रोडमैप है। चर्चा के दौरान जैसे ही अनुराग ठाकुर जवाब देने के लिए खड़े हुए कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया। इस पर टिप्पणी करते हुए ठाकुर ने कहा, 'जब हम बोलते हैं तो राहुल गांधी सामना नहीं कर पाते। पहले हमारे भाषण के बीच में जाते थे, अब तो पहले ही चले गए।'

राहुल गांधी ने लोकसभा में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को बताया समर्पण

लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को केंद्र सरकार का ट्रंप प्रशासन के आगे समर्पण करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इस डील में भारतीय डेटा,किसानों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता अमेरिका के हवाले कर दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि दुनिया स्थिरता से अस्थिरता की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष, मिडिल ईस्ट में तनाव और ईरान के साथ युद्ध की आशंका ने माहौल को खतरनाक बना दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार खुद मानती है कि अमेरिका-केंद्रित पुराना बहुध्रुवीय सिस्टम टूट रहा है। डॉलर का वर्चस्व चुनौती का सामना कर रहा है, चीन और रूस जैसी ताकतें इसे चुनौती दे रही हैं। ऊर्जा और वित्त को हथियार बनाया जा रहा है। डॉलर कमजोर हो रहा है और सोना-चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। एनएसए ने कुछ समय पहले कहा था कि युद्ध का दौर खत्म हो गया है लेकिन अब हम युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने भारत की तीन सबसे बड़ी ताकतें गिनाते हुए कहा कि हमारी पहली ताकत है हमारे 1.4 अरब लोग जो ऊर्जावान और प्रतिभाशाली हैं। दूसरी ताकत है इनसे बनने वाला विशाल डेटा पूल। 21वीं सदी में जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि लोग डेटा बनाते हैं और डेटा ही एआई का ईंधन है। भारत का डेटा पूल दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे विविध है। तीसरी ताकत है हमारे किसान और मजदूर जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ऐसे तूफानी दौर में इन तीन चीजों को बचाना सबसे जरूरी है। लोग और उनका डेटा,खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा प्रणाली।

उन्होंने कहा कि एआई का दौर आ रहा है और इसके खतरनाक परिणाम होंगे। भारतीय आईटी उद्योग और लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर खतरे में पड़ सकते हैं। एआई कई नौकरियों को खत्म कर देगा। ऐसे समय में सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था लेकिन बजट में इनमें से किसी पर ठोस प्रावधान नहीं है। राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कहा कि फरवरी 2026 में ट्रंप और मोदी की बातचीत के बाद यह डील घोषित हुई। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाया लेकिन बदले में भारत ने कई शर्तें मान लीं। असली लड़ाई भारतीय डेटा के लिए है और सरकार ने इसे बिना सुरक्षा के अमेरिका को सौंप दिया। डिजिटल ट्रेड नियमों पर नियंत्रण छोड़ दिया गया, डेटा लोकलाइजेशन की जरूरत खत्म कर दी गई, अमेरिकी कंपनियों को मुक्त डेटा प्रवाह और 20 साल का कर छूट (टैक्स हॉलीडे) घोषित दिया गया। राहुल ने कहा कि भारतीय टैरिफ औसतन 3 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया जबकि अमेरिकी टैरिफ 16 प्रतिशत से शून्य हो गया।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने माना-एपस्टीन से 3-4 मुलाकातें हुई

मीटिंग प्रोफेशनल,यौन अपराधी से संबंध का आरोप बेबुनियाद,राहुल ने संसद में नाम लिया था

ई दिल्ली,11 फरवरी 2026। ंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने धवार को कहा कि वह यौन पराधी जेफ्री एपस्टीन से तीन या ार बार मिले थे। यह बातचीत पूरी रह से प्रोफेशनल थी,जो इंडिपेंडेंट मीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म ौर दूसरे इंटरनेशनल कामों से ुड़ी थी। पुरी ने बुधवार को नेता तिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में पस्टीन विवाद में उनका नाम लेने ह बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पस्टीन के आपराधिक मामलों से पना कोई संबंध होने के आरोपों ो बेबुनियाद बताया। पुरी ने कहा, ब मैंने मई 2009 से न्यूयॉर्क में ंयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के प में कार्यभार संभाला था, तब से ेकर 2017 में मंत्री बनने तक ी अवधि के 30 लाख ईमेल ारी किए गए हैं। इस दौरान, ेवल तीन या चार बैठकों का ही

जिक्र मिलता है और मेरी बातचीत पूरी तरह से पेशेवर थी। दरअसल, राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में एपस्टीन फाइल्स को लेकर पुरी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था...अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका नाम एपस्टीन फाइल्स में है। मैं जानता हूं कि उनको एपस्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। पुरी ने यह भी बताया कि वे लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन से भी मिले थे, लेकिन यह मुलाकात भारत में इंटरनेट और कारोबार के अवसरों पर पेशेवर चर्चा के लिए थी। पुरी ने साफ कहा कि इन मुलाकातों का किसी भी तरह की गलत गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं था।

जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम

सभी 6 पैरा गाना जरूरी,स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई,सिनेमाघरों को छूट

नई दिल्ली,11 फरवरी 2026। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में 'वंदे मातरम' बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ,लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक,आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' साथ में गाए या बजाए जाएं,तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार,राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब तक मूल गीत के पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे। हालांकि,आदेश में यह भी कहा गया है किन-किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है,इसकी पूरी लिस्ट देना

संभव नहीं है। यह पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहा है।

राष्ट्रपति के आगमन और झंडारोहण जैसे कार्यक्रमों में गाया जाएगा : नई गाइडलाइन के अनुसार,तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में,और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर-औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए। 10 पेजों के आदेश में, सिविलियन पुरस्कार समारोहों,जैसे कि पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हों, वहां भी वन्दे मातरम बजाया जाएगा।

सिनेमा हॉल में लागू नहीं होंगे नए नियम

हालांकि,सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है। यानी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले 'वंदे मातरम' बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं अगर किसी न्यूजरील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है, तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि अब से राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया या बजाया जाएगा और इसे सामूहिक गायन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

भाजपा की रितु तावड़े बनीं मुंबई की नई मेयर शिवसेना के संजय घाड़ी बने उप महापौर

मुंबई,11 फरवरी 2026। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पार्षद रितु तावड़े बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की निर्विरोध महापौर चुनी गई हैं। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद संजय घाड़ी उपमहापौर बने हैं। इसकी घोषणा बुधवार को बीएमसी मुख्यालय में निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने की। आयुक्त गगरानी ने कहा कि महापौर पद के लिए केवल भाजपा पार्षद रितु तावड़े का ही नामांकन प्राप्त हुआ था,इसलिए उन्हें बीएमसी का महापौर घोषित किया जाता है। इसी तरह,उपमहापौर पद के लिए केवल संजय घाड़ी का ही नामांकन प्राप्त हुआ,इसलिए उन्हें उपमहापौर घोषित किया जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने रितु तावड़े और संजय घाड़ी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महापौर तावड़े और उपमहापौर घाड़ी शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे और राज्य सरकार इस कार्य में उनका पूरा सहयोग करेगी।

सरकार बोली-वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा नहीं कर सकते..सुप्रीम कोर्ट में कहा-उनकी जेल में 24 बार जांच हुई,वे पूरी तरह फिट

नई दिल्ली,11 फरवरी 2026। सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वांगचुक को फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सरकार से वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा करने के बारे में पूछा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की जेल नियमावली के तहत अब तक करीब 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वांगचुक पूरी तरह फिट हैं। उन्हें केवल डाइजेशन (पाचन) की समस्या और संक्रमण हुआ था, जिसका इलाज किया गया है। मेहता ने कहा कि इस तरह की समस्या को अपवाद मानकर उन्हें रिहा किया गया तो आगे अन्य लोग भी इस तरह की मांग करेंगे।

अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू,रेलवे बोर्ड का आदेश जारी

नई दिल्ली,11 फरवरी 2026। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों और क्रिस (सीआरआईएस) के प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार,पूर्व में 15 जनवरी के निर्देशों के तहत इन ट्रेनों में केवल महिला कोटा, दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) कोटा, वरिष्ठ नागरिक कोटा और ड्यूटी पास कोटा ही लागू था तथा अन्य किसी प्रकार का आरक्षण कोटा, जिसमें आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) भी शामिल

है, लागू नहीं था। मामले की समीक्षा के बाद अब इन ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार, जिन अमृत भारत ट्रेनों में 7 या उससे अधिक स्लीपर (एसएल) कोच हैं,उनमें अधिकतम 24 बर्थ का इमरजेंसी कोटा निर्धारित किया जा सकता है। वहीं, वंदे भारत स्लीपर (वीबीएस) ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों के लिए इमरजेंसी कोटा तय किया गया है। इसके तहत सप्ताह के दिनों में प्रथम श्रेणी एसी (1ए) में 4, सप्ताहांत में 6; द्वितीय एसी (2ए) में सप्ताह के दिनों में 20, सप्ताहांत में 30 तथा तृतीय एसी (3ए) में सप्ताह के दिनों में 24 और सप्ताहांत में 42 बर्थ इमरजेंसी कोटे के तहत निर्धारित की जा सकती हैं।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह कोटा अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) या बुकिंग शुरू होने की तिथि से, जो भी पहले हो, लागू किया जा सकेगा। साथ ही, अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह जोनल रेलवे मांग और उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर इमरजेंसी कोटे की समीक्षा कर आवश्यक समायोजन कर सकेंगे।

राहुल गांधी का संसद में रवैया सुस्त और गैर-जिम्मेदाराना : भाजपा

नई दिल्ली,11 फरवरी 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए तथ्यों को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज करते हुए उन्हें गैर-जिम्मेदाराना बताया। बुधवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले ज़हरीले झूठ फैलाते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं। संसदीय कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी का रवैया सुस्त और गैर-जिम्मेदाराना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में कांग्रेस पार्टी का व्यवहार सड़क पर होने वाले प्रदर्शन जैसा रहा, जो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि उन्होंने देखा कि जब कुछ लोग तख्तियां लेकर

ट्रेज़री बेंच की ओर बढ़ रहे थे, तो महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसकी याद उन्हें शाहीन बाग की घटनाओं से जुड़ी प्रतीत हुई। उन्होंने कहा कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है, लेकिन अगर आपको सड़कछाप भाषा और सड़कछाप आचरण संसद में देखना हो तो, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है।

राजस्थान बजट : 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी,पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई घोषणाएं

जयपुर,11 फरवरी 2026। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने राज्य में आठवें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी गठित करने की घोषणा की। प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। स्कूली बच्चों को खेल किट और 'जादुई पिटारा' उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसे मरीजों को भी निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है। पर्यटन क्षेत्र में जैसलमेर के खुरी में विशेष पर्यटन क्षेत्र (एसटीजेड) स्थापित किया जाएगा। कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। पुष्कर, खाटू श्यामजी, देशनोक, डिग्गी और मंडावा में प्रवेश मार्गों को मॉडल सड़क के रूप में विकसित कर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से ब्रज कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य में चिन्हित बावड़ियों के संरक्षण और पुनरुद्धार का कार्य किया जाएगा।

ममता पहली सीएम हैं जो अपने ही कर्मचारियों को डीए न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची : भूपेंद्र यादव

कोलकाता,11 फरवरी 2026। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने ही सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। कोलकाता में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कई लोगों की मौत का आरोप लगाया था, जबकि वास्तव में इस प्रक्रिया के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि राज्य के कई कर्मचारी वर्षों से बकाया महंगाई भत्ता नहीं मिलने से निराश थे। पत्रकार

वार्ता में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर मीडिया के सवालों से बचने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री यह कहकर जवाब देने से बच रही हैं कि मामला विचाराधीन है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह स्पष्ट आदेश दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को 2008 से 2019 के बीच के महंगाई भत्ता बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही कुल बकाये की 25 प्रतिशत राशि इस वर्ष 31 मार्च तक चुकाने को कहा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी आदेश की अवहेलना की गई तो कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि, उच्चतम न्यायालय ने पांच फरवरी को अपने फैसले में राज्य सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया था।

संपादकीय

एआई के खतरों से रहें सावधान

हमें समझना होगा कि एआइ कोई प्रतिस्पर्धी लाभ नहीं,बल्कि एक साझा दायित्व है। वसुधैव कुटुंबकम् का भारतीय विचार अब दर्शन के दायरे से निकलकर अस्तित्व की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में, भारत अपनी सभ्यतागत गहराई और विश्वसनीयता के माध्यम से नए शासकीय ढांचों के लिए वैश्विक एआइ मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है...

पिछले एक दशक के दौरान दुनिया जितनी तेजी से बदली है, उसे देखते हुए अगले दस-बीस वर्षों के संभावित परिवर्तनों की थाह लेना आवश्यक हो गया है। मानव इतिहास के अधिकांश दौर में अभाव जैसे पहलू ने ही सभ्यताओं का तानाबाना रचा है। फिर चाहे यह खानपान का अभाव हो,जमीन,श्रम,पूंजी या कालांतर में ज्ञान का। हमारे आर्थिक सिद्धांतों का उद्भव एवं राजनीतिक संस्थानों का विकास भी अभाव प्रबंधन पर केंद्रित रहा।

मशीनी कौशल यानी एआइ में इस पारंपरिक परिदृश्य को पलटने की क्षमता है। यदि बीसवीं सदी अभावों से पार पाने से जुड़ी थी तो आने वाला दशक अधिशेष के साथ संतुलन की चुनौती के नाम हो सकता है। नए परिदृश्य में तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है,उस लिहाज से हमारी संस्थाएं पिछड़ती जा रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उन नीतिगत उपायों पर विचार किया जाए जो एआइ से उत्पन्न उथल-पुथल से निपटने में कारगर साबित हो सकें।

पारंपरिक अर्थशास्त्र में उत्पादन के चार प्रमुख कारक-श्रम, पूंजी, भूमि और तकनीक माने गए हैं। तकनीक ने हमेशा श्रम को सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक तकनीकी संक्रमण उत्पादकता एवं पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ ही मांग के विस्तार और नई नौकरियों का माध्यम बना है। इससे कुछ असुविधा होती भी थी तो बस तात्कालिक ही न कि स्थायी, मगर एआइ से यह रुझान पलट सकता है। पहली बार तकनीक सीधे तौर पर श्रम को प्रतिस्थापित करती दिख रही है।

न केवल शारीरिक श्रम,बल्कि बौद्धिक,पेशेवर और रचनात्मक कामकाज के मामले में भी एआइ प्रभुत्व दिखा रही है। एआइ के साथ उत्पादकता तो बढ़ रही है, पर रोजगार सृजन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इससे साझा समृद्धि की राह प्रशस्त होने से रही। यानी विषमता बढ़ेगी। प्रकृति और स्वरूप में भी एआइ पिछली तकनीकों की तुलना में अलग है। इसका कोई प्रतिरूप एक बार आकार लेने पर यह सीमांत लागत को शून्य तक करने में सक्षम है। यह स्वाभाविक रूप से एकाधिकार की स्थिति निर्मित करता है। कुछ देशों की चुनिंदा कंपनियों द्वारा विशेष प्रतिरूपों में महारत हासिल करने से यह झलकता भी है।

तमाम विश्लेषकों को आशंका सता रही है कि एआइ बड़े स्तर पर हलचल मचा सकती है। यह मानव समाज के संतुलन को भी प्रभावित करने में सक्षम है। आज उत्पादकता और क्षमताएं निरंतर बढ़ रही हैं। वस्तुएं सस्ती हो रही हैं। सेवाओं का स्तर सुधरा है। भौतिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। एआइ को सफलतापूर्वक अपनाने वाले देश तेज आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और बीमारियों पर बोझ घट रहा है। जीवन के विस्तार और काम का दायरा सिकुड़ने पर जननांकीय लाभांश अपने अर्थ खो देता है।

इस परिदृश्य में विदेश से भेजी जाने वाली धनराशि पर निर्भर राष्ट्र-समाज समस्याओं का सामना करते हैं। तब गरिमा और आजीविका के आधार के रूप में रोजगार का विचार संकट का शिकार होने लगता है। संसाधनों का संकेंद्रण भी एआइ के मोर्चे पर पैदा होने वाली एक और समस्या है। ऐसे में संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए कोई कारगर नीतिगत उपाय खोजना ही होगा। इसके अभाव में व्यापक आर्थिक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है।

एआइ के चलते सीखने-समझने की क्षमताओं पर भी संकट मंडराता दिख रहा है। जब मशीन ही फैसले लेने में भूमिका निभाने लगेगी तो लोगों में सीखने के प्रति झुकाव घटने का अंदेशा बढ़ता है। इतिहासकार डेविड रोकलिन ने यह रेखांकित भी किया था कि आटो-पायलट मोड पर अत्यधिक निर्भरता संकट के समय पायलटों के हाथ-पांव फुला देती है। बड़ा खतरा यह नहीं कि मशीन किसी इंसान की भांति काम करे, बल्कि यह खतरा कहीं विकराल होगा कि इंसान ही मशीन की तरह व्यवहार करने लगे।

एआइ की वजह से फर्जी सूचनाओं और तमाम संदिग्ध सामग्री का सैलाब भी संकट बढ़ा रहा है। इससे भरोसे की भावना पर आघात पहुंचा है। सत्य और मिथ्या को लेकर ऐसा जाल बुना जा रहा है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। एआइ पर पकड़ रखने वाले और ताकतवर बनने की राह पर हैं। इसके दम पर नव-धनकुबेरों का उभार हो रहा है।

भू-राजनीतिक संदर्भ में भी एआइ विषमता बढ़ा रही है,क्योंकि आधुनिक तकनीक से वंचित देश स्वतः पिछड़ते जाएंगे। किसी देश की संप्रभुता पर किसी अन्य देश से संचालित हो रहे एलगोरिदम से ग्रहण लग सकता है। इस सबके बावजूद अगर सही नीतिगत उपाय किए जाएं तो एआइ बहुत सकारात्मक परिवर्तन भी कर सकती है। इसके लिए एआइ को तकनीकी उपकरण से अधिक सभ्यतागत शक्ति के रूप में देखना होगा। एआइ का उपयोग मानव की जगह लेने के बजाय उसकी क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए।

एआइ उन तमाम समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, जिसके लिए असाधारण मानवीय प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि बाहरी-अंतरिक्ष में कोई नया मोर्चा खोलना, गहरे समुद्र या पृथ्वी की जटिल परतों के रहस्यों को सुलझाना। इससे कई ग्रहों पर मानवीय जीवन को संभव बनाया जा सकता है।

एप्सटिन फ़ाइल्स : शर्म,सन्नाटा और हमारी सामूहिक विफलता

डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

सत्ता-संरक्षित अपराधों के सामने समाज,मीडिया और न्याय की सामूहिक परीक्षा

इतिहास के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सभ्यता अपने ही आईने में झाँकने से डरने लगती है। आज हम ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। जिन कांडों का खुलासा हो रहा है–जिनके वीडियो,दस्तावेज़ और गवाह सार्वजनिक हो चुके हैं–वे महज़ अपराध नहीं हैं,बल्कि मानवता के विरुद्ध सुनियोजित,संरक्षित और सत्ता-समर्थित हमले हैं। इन घटनाओं की भयावहता इतनी गहरी है कि शब्द भी लड़खड़ा जाते हैं। फिर भी समाज इन्हें कंटेंट की तरह उपभोग कर रहा है–चाव,रोमांच और क्षणिक घृणा के साथ–और फिर अगली सनसनी की ओर बढ़ जाता है। यह कोई नई कहानी नहीं है। हर बड़े घोटाले,हर सामूहिक अपराध के बाद यही क्रम दोहराया गया है–पहले इनकार,फिर आंशिक स्वीकारोक्ति,उसके बाद माफ़ी या इस्तीफ़ा, और अंततः कम्पैरिटिवली बेहतर का आत्मसंतोष। मानो न्याय कोई तुलनात्मक पैमाना हो,जहाँ कम बुरा होना ही अच्छा होने का प्रमाण बन जाए। पर असली सवाल कहीं गहरा है–जब अपराध हो रहे थे,तब आत्मा कहाँ थी? क्या नैतिकता केवल कैमरों के सामने ही जागती है?

इन कांडों की सबसे भयावह परत सत्ता से जुड़ी है। उच्चतम पदों पर बैठे लोग–जिन्हें समाज ईश्वरतुल्य मानता है–जब दोषियों से संवाद करते,उन्हें संरक्षण देते,उनसे लाभ लेते या उनके लिए रास्ते बनाते पाए जाते हैं,तब लोकतंत्र की बुनियाद हिल जाती है। यह व्यक्तिगत नैतिक पतन नहीं,बल्कि संस्थागत अपराध है। क्योंकि जब अपराध को व्यवस्था का संरक्षण मिलता है, तब वह अपवाद नहीं रहता–वह एक प्रणाली बन जाता है।

मीडिया की भूमिका यहाँ निर्णायक होनी चाहिए थी। लेकिन अक्सर वह भी दो ध्रुवों में बँटी नज़र आती है–एक ओर सनसनी,दूसरी ओर चुप्पी। सनसनी पीड़ितों की गरिमा को रौंदती है,जबकि चुप्पी अपराधियों को समय और सुरक्षा देती है। टीआरपी,क्लिक और ट्रेंड की दौड़ में सत्य दम तोड़ देता है। नतीजा यह कि जनता को तथ्य नहीं, भावनात्मक झटके मिलते हैं–और झटकों से स्थायी सामाजिक कार्रवाई कभी जन्म नहीं लेती।

क़ानून और जाँच एजेंसियों की स्थिति भी कोई आश्वस्ति नहीं देती। धीमी जाँच,अधिकार-क्षेत्र की उलझनें, राजनीतिक दबाव और अंतहीन प्रक्रियाएँ–ये सब मिलकर न्याय को टालने की एक सुव्यवस्थित मशीन बना देते हैं। कहा जाता है कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान होती है; यहाँ यह कहावत एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आती है। पीड़ित थक जाते हैं, गवाह डर जाते हैं और अपराधी समय के साथ और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।

सबसे असहज प्रश्न फिर भी आम जनता से जुड़ा है। क्या सचमुच हमें लकवा मार गया है? या हमें इस तरह ढाला गया है कि हम क्रोधित तो हों, पर संगठित न हो सकें? सोशल मीडिया हमें आवाज़ देता है, लेकिन दिशा नहीं। हम पोस्ट करते हैं, साझा करते हैं, गालियाँ देते हैं और यह मान लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। वास्तविक दुनिया में उतरने का धैर्य,जोखिम और निरंतरता–ये सब दुर्लभ होते चले गए हैं। यह भी एक सच है कि जनता को थकाने की बाक़ायदा रणनीति अपनाई जाती है। सूचनाओं की बाढ़, विरोधाभासी दावे,फर्जी खबरें और आधे-अधूरे सच–इन सबके ज़रिये भ्रम पैदा किया जाता है। और भ्रम से निष्क्रियता जन्म लेती है। निष्क्रिय समाज अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण होता है।

कुछ देशों में माफियाँ माँगी जा रही हैं,कहीं इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं और इन्हें बड़ी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन माफ़ी तभी मायने रखती है जब उसके साथ जवाबदेही हो–क़ानूनी कार्रवाई,संपत्ति की जब्ती,नेटवर्क का खुलासा और स्थायी संस्थागत सुधार। केवल चेहरे बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती। इस्तीफ़ा न्याय नहीं है,वह अधिकतम उसकी शुरुआत हो सकता है।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक उपेक्षित पक्ष पीड़ितों का है। उनकी कहानियाँ,उनका दर्द और उनका पुनर्वास–सब कुछ हाशिये पर धकेल दिया जाता है। जबकि न्याय का अर्थ केवल सज़ा नहीं है,न्याय का अर्थ है पीड़ित की जिंदगी को दोबारा खड़ा करना। काउंसलिंग, चिकित्सा,शिक्षा,रोज़गार और गवाह सुरक्षा–ये सब उतने ही आवश्यक हैं जितनी अदालत की कार्यवाही। इनके बिना न्याय हमेशा अधूरा रहेगा।

तो रास्ता क्या है? प्रतिशोध नहीं। हिंसा की कामना हमें उन दरिंदों से अलग नहीं बनाती जिनसे हम घृणा करते हैं। सभ्यता की जीत क्रूरता से नहीं,बल्कि जवाबदेही से होती है। इसके लिए कुछ बुनियादी बिंदुओं पर समाज को एकजुट होना होगा।

पहला,स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय जाँच,क्योंकि सीमा-पार और सत्ता-समर्थित अपराधों में केवल राष्ट्रीय एजेंसियाँ पर्याप्त नहीं होतीं। दूसरा, पूर्ण प्रकटीकरण–नाम,पद,नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन का सार्वजनिक खुलासा। तीसरा, क़ानूनी सुधार–विशेष अदालतें,समयबद्ध सुनवाई और मज़बूत गवाह सुरक्षा क़ानून। चौथा, जिम्मेदार मीडिया,जो पीड़ित-केंद्रित, तथ्यपरक और निरंतर रिपोर्टिंग करे। पाँचवाँ, नागरिक एकजुटता–शांतिपूर्ण, संगठित और लगातार दबाव। क्योंकि बदलाव किसी एक पोस्ट से नहीं, बल्कि निरंतरता से आता है।

अंततः यह लड़ाई नैतिकता की है। हर समाज को कभी न कभी यह तय करना पड़ता है कि वह सुविधा चुनेगा या सत्य। सुविधा हमें सुला देती है, जबकि सत्य हमें बेचैन करता है–और इतिहास हमेशा उसी बेचैनी से आगे बढ़ता है। लानत दरिंदों पर तो बनती है। लेकिन इतिहास हमें इस आधार पर परखेगा कि क्या हमने अपने आक्रोश को क्षणिक नफ़रत में गँवा दिया,या उसे परिवर्तन की संगठित ताक़त में बदला। चुप्पी अब विकल्प नहीं है। देर से सही, पर न्याय आना चाहिए–और ऐसा न्याय, जो केवल दोषियों को दंडित न करे, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाए। यही इस समय की सबसे बड़ी माँग है। और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।

साहस और विनम्रता जीवन की सच्ची महक

संजीव ठाकुर,
रायपुर,छत्तीसगढ़,

जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति और सफलता के लिए मनुष्य को निरंतर कर्म की प्रधानता रखकर संयम तथा मनोबल भी रखना होगा । इसके अलावा मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास ना होकर उस पर नियंत्रण रख स्वामी बनने का प्रयास करना होगा तब सोची गई सफलता आपके सामने होगी।

कठिन तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अपने मनोबल को सदैव विनम्रता,संयम और साहस के साथ ऊंचा रखना चाहिए।अपने द्वारा की गई मेहनत पर विश्वास एवं निरंतरता रखनी होगी। तब जाकर ही जीवन में सफलता के पल आपके सामने आएंगे। निराशा,हताशा और हीन भावना को कठोर श्रम के बलबूते पर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। जीवन में उतार-चढ़ाव,कठिन समय और विषम परिस्थितियां आती ही रहती हैं। संकट का समय विषम परिस्थितियां जीवन के अलग-अलग पहलू हैं ।इनसे जूझ कर जो मानव आगे बढ़ता है,वह उच्च मनोबल वाला साहसी व्यक्ति होता है। व्यक्ति के जीवन में साहस,उच्च मनोबल ही सफलता की कुंजी है। जिस भी व्यक्ति ने विषमताओं में रास्ता निकलने का साहस करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है वही सफल हुआ है। हमेशा सफलता का मूल आत्मविश्वास,कठिन श्रम और उच्च आदर्श वाले व्यक्ति की प्रेरणा ही सफलता दिलाने वाली होती है। मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मन से हार नहीं माननी चाहिए। उसे सदैव प्रयासरत रहकर परिश्रम तथा जुझारू पन से हर परिस्थिति का सामना कर सदैव अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी हर हार,हर पराजय से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए एवं इससे अनुभव प्राप्त कर फिर से खड़ा होने एवं उस पराजित मनोदशा से छुटकारा पाकर फिर से लड़ने की ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करनी चाहिए,यह सफलता का बड़ा मंत्र है। सर्वप्रथम मनुष्य अपने मनोबल से किन्हीं भी परिस्थितियों को जीतने का साहस रखता है, इसीलिए मनोबल मनुष्य की पहली आवश्यकता है। मनोबल ही साहस को जन्म देता है और साहस, आत्मबल को और आत्मबल से ही मनुष्य किन्हीं भी परिस्थितियों से जूझना एवं टकराने की क्षमता पैदा करता है। जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ ना हो तो वह निश्चिंत होकर साहस,क्षमता एवं संयम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है,क्योंकि वह जानता है की पीछे पलट कर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, शिवाय आगे बढ़ने एवं

सफलता के लिए अग्रसर होने के। मनुष्य का मनोबल एवं दृढ़ प्रतिज्ञा ही मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। मनुष्य के जीवन का एक तथ्य और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है सकारात्मक सोच,जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की ओर उत्साहित करती रहती है। सकारात्मक सोच एवं किसी भी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाने की सुनियोजित योजना मनुष्य में आशाओं को भर देती है एवं परिस्थितियों को चुनौती देने की क्षमता का विकास करती है। यह मनुष्य ही है जो हर परिस्थिति में साहस और मनोबल के दम पर उससे विजय प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन और पशु के जीवन में यही फर्क है कि मनुष्य के पास सोचने के लिए मस्तिष्क होता है और वह उसके सकारात्मक उपयोग के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। मनुष्य मुस्कुराता,हंसता और खिलखिलाता है। जबकि पशु में मुस्कुराने हंसने की क्षमता नहीं होती, और यही कारण है कि मनुष्य ने विषम परिस्थितियों पर सदैव विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है,वह काफी हद तक सफलता पाने में सफल भी हुआ है। मनुष्य यदि परिस्थितियों में अन्य प्रतियोगिताओं में,खेल में,या युद्ध में पराजित होकर भी प्रेरणा लेकर पुनः साहस के साथ पुनःतैयार होता है तो वह आने वाले समय में सफलता का सही हकदार भी होता है,क्योंकि उसने पूरी क्षमता,साहस,मनोबल के साथ पराजय को स्वीकार कर के उससे कुछ सीखने का प्रयास किया है। अपनी कमियों को दूर करने की हर संभव कोशिश भी की है ।इस तरह वह अगली परीक्षा में जरूर सफल होता है और यही मानव जीवन का सफल अध्याय भी होता है। कुल मिलाकर परिस्थितियां तथा घटनाएं,दुर्घटनाएं मनुष्य को परिस्थितियों के सामने पराजित करने,झुकाने की कोशिश करती हैं किंतु मानव अपने शारीरिक, मानसिक,नैतिक,चारित्रिक एवं मानसिक आत्मबल से उसे सफलता में बदल देता है। अनवरत प्रयासरत व्यक्ति अपने साहस परिश्रम से हर चुनौतियों का सामना कर परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर अपने जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों से जूझ कर जो मानव सदैव सफल होता है वह पूरे समुदाय और समाज के लिए एक प्रेरणादाई व्यक्तित्व बन कर पूरे समाज एवं देश को मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।इसीलिए मनुष्य को किन्हीं भी परिस्थितियों में, खासकर विषम परिस्थितियों में अपने मनोबल और साहस को त्यागना नहीं चाहिए। उच्च मनोबल और साहस की ऊर्जा ही मनुष्य को नई दिशा, नए प्रकाश पुंज की ओर अग्रसर करती है।

योगी के बजट से 2027 की बिसात,आंकड़ों के सहारे सियासी दांव

अजय कुमार
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट केवल अगले वित्त वर्ष की आय-व्यय योजना नहीं है, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे ठोस राजनीतिक पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के इस बजट के जरिए सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वह चुनाव से पहले विकास, सुरक्षा और कल्याण तीनों मोर्चों पर अपने दावों को आंकड़ों के साथ जमीन पर उतारकर पेश करना चाहती है। पिछले बजट के मुकाबले करीब 12.9 प्रतिशत बड़े इस आकार को सत्ता पक्ष विश्वास का बजट बता रहा है, जबकि इसके भीतर छिपा राजनीतिक संदेश यह है कि सरकार न तो संसाधनों की कमी से जूझ रही है और न ही चुनाव से पहले खर्च बढ़ाने से पीछे हट रही है।

सरकार ने सबसे पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने मजबूत पक्ष के रूप में सामने रखा है। 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार 30.25 लाख करोड़ रुपये की जीएसडीपी और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर यह दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या वाला राज्य नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है। 2016-17 में जहां जीएसडीपी करीब 12.75 लाख करोड़ रुपये थी,वहीं आठ-नौ वर्षों में इसके ढाई गुना से अधिक होने को सरकार स्थिर शासन और निवेश के अनुकूल माहौल का नतीजा बता रही है। 2027 के चुनाव में यह आंकड़ा खासतौर पर शहरी मतदाताओं, कारोबारियों और निवेश से जुड़े वर्गों के सामने रखा जाएगा,ताकि यह संदेश जाए कि सत्ता में बदलाव विकास की रफ्तार को रोक सकता है। प्रति व्यक्ति आय को लेकर दिए गए आंकड़े भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। 2016-17 में 54,564 रुपये रही प्रति व्यक्ति आय के 2024-25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये होने और 2025-26 में इसके 1,20,000 रुपये तक पहुंचने के अनुमान को सरकार आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर पेश कर रही है। यह संदेश खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, जो महंगाई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्च को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। सरकार का दावा है कि आय बढ़ने का मतलब सिर्फ आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि उपभोग और जीवन स्तर में बदलाव है।

गरीबी के मोर्चे पर 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का दावा 2027 के लिहाज से सबसे बड़ा सामाजिक कार्ड माना जा रहा है। मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन,आयुष्मान भारत कार्ड, शौचालय और बिजली कनेक्शन जैसी योजनाओं से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों को एक साथ रखकर सरकार यह दिखाना चाहती है कि गरीब सिर्फ योजनाओं का नाम नहीं,बल्कि सत्ता की राजनीति का केंद्र है। चुनावी रणनीति में यह वर्ग इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे सरकार से जुड़ाव महसूस करता है और उसके फैसले अक्सर स्थिर रहते हैं।

रोजगार को लेकर बजट में पेश किए गए आंकड़े विपक्ष के सबसे मजबूत मुद्दे का जवाब माने जा रहे हैं। बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत बताकर सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में रोजगार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पुलिस विभाग में 2017 से अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक भर्तियां,1 लाख 58 हजार पदोन्नतियां,60 हजार से ज्यादा प्रशिक्षणाधीन जवान और 83 हजार से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को एक साथ जोड़ कर सरकार यह दिखाना चाहती है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहीं। शिक्षा क्षेत्र में 34 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी दिशा में रखा गया कदम है, क्योंकि शिक्षक समुदाय ग्रामीण और कस्बाई राजनीति में राय बनाने की अहम भूमिका निभाता है।

युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति भी बजट में साफ दिखती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज ऋण देकर हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका राजनीतिक मतलब यह है कि सरकार उन युवाओं को भी साधना चाहती है,जिन्हें सरकारी नौकरी की सीमित सीटों से निराशा हुई है। अगर यह योजना आंशिक रूप से भी सफल होती है, तो 2027 तक लाखों परिवार सीधे इससे जु सकते हैं।

कृषि क्षेत्र के आंकड़े ग्रामीण राजनीति को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। 3 लाख 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में सरकार का सबसे मजबूत चुनावी हथियार माना जा रहा है। गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी से करीब 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ का दावा किसानों को यह याद दिलाने के लिए है कि भुगतान सीधे खाते में पहुंचा है। गेहूं,धान और मोटे अनाज की लाखों मीट्रिक टन खरीद और हजारों करोड़ रुपये के भुगतान के आंकड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश हैं। नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था ग्रामीण मतदाताओं के लिए सीधा संदेश है कि सिंचाई लागत सरकार उठाने को तैयार है। महिलाओं को लेकर बजट में दिए गए आंकड़े 2022 के चुनावी अनुभव से निकले हुए माने जा रहे हैं,जहां महिला मतदाताओं का झुकाव निर्णायक साबित हुआ था। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बालिकाओं को लाभ,सेफ सिटी परियोजना,महिला पुलिस बीट,सीसीटीवी नेटवर्क और वर्किंग वूमेन हॉस्टल जैसे प्रावधान यह दिखाते हैं कि सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान को केवल कानून-व्यवस्था नहीं,बल्कि सामाजिक मुद्दा मानती है। महिला मतदाता भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर निर्णय करती हैं,और बजट में यह संदेश उसी दिशा में जाता है।

कानून-व्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी 2027 की चुनावी कहानी का अहम हिस्सा हैं। डकैती,लूट,हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में 40 से 80 प्रतिशत तक कमी के दावे के जरिए सरकार यह स्थापित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा असुरक्षित नहीं है। पुलिस भवनों, आवास और संसाधनों पर हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। यह संदेश शहरी मतदाताओं, व्यापारियों और महिलाओं के लिए खास तौर पर अहम है।

कुल मिलाकर 2026-27 का बजट एक ऐसा दस्तावेज बनकर सामने आया है,जिसमें हर बड़ा आंकड़ा 2027 के मतदाता को ध्यान में रखकर चुना गया है। विकास,कल्याण, सुरक्षा और पहचान चारों को जो कर सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सत्ता की निरंतरता ही स्थिरता की गारंटी है। आने वाले महीनों में यही बजट गांव-गांव,शहर-शहर होने वाली राजनीतिक बहसों का आधार बनेगा,जहां सरकार इन आंकड़ों के सहारे भरोसा मांगेगी और विपक्ष इन्हीं आंकड़ों को चुनौती देने की कोशिश करेगा।

हाय रे मोटापा...

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

छंगामलपुर के पावन परिक्षेत्र में वजन नापने की मशीन दरअसल उन लोगों का खिलौना है जिनके पास जीवन में कोई ठोस उद्देश्य नहीं बचा है। यहाँ समृद्धि को अंकों में नहीं,बल्कि कमर के भव्य घेरे में नापा जाता है। तहसील के गलियारों में किसी को मोटा कहना गाली नहीं,बल्कि एक चारित्रिक प्रमाण-पत्र है जो इस बात की पुष्टि करता है कि संबंधित व्यक्ति ने सार्वजनिक सेवा की वैतरणी को सफलता पूर्वक पार कर लिया है और अब उसके पास इतना अधिशेष है कि उसे संभालने के लिए एक विशेष दर्जी और दो-तीन अतिरिक्त कुर्सियों की आवश्यकता है। इसके विपरीत,एक दुबले आदमी को यहाँ गहरी संशय की दृष्टि से देखा जाता है। अगर आप दुबले हैं,तो या तो आप व्यवस्था को उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारी हैं, या फिर ईमानदारी के किसी जानलेवा दौरे से गुजर रहे हैं। दुबला आदमी स्थानीय प्रशासनिक प्रोटोकॉल के लिए एक खतरा है, क्योंकि उसकी फुरती यह संकेत देती है कि वह काम निपटाने के लिए दौड़ भी सकता है, जो कि यहाँ की स्थिरता वाली संस्कृति का सीधा अपमान है।

गयादीन का पेट अब उनके शरीर का हिस्सा नहीं,बल्कि एक स्वायत्तशासी निकाय बन चुका है जो अपनी मर्जी से फैसले लेता है। जब वे बैठते हैं,तो उनका उदर उनकी जाँघों पर इस तरह विराजमान होता है जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक की गोद में अपनी जगह पक्की कर चुका हो। उनके लिए चलना कोई शारीरिक क्रिया नहीं,बल्कि एक भारी भरकम लॉजिस्टिक चुनौती है–एक लयबद्ध डगमगाहट, जो देखने वाले को किसी टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने का आभास कराती है। उनके कुर्ते के चाक हर रोज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं, जो आगे और पीछे के पल्लों के बीच बढ़ते हुए भौगोलिक फासले को पाटने की कोशिश में अपनी आखिरी साँसें गिनते रहते हैं।

वे आधुनिक डॉक्टर, जो स्टेथोस्कोप लटकाए कोलेस्ट्रॉल का डर फैलाते फिरते हैं, दरअसल जीवन की चाशनी में घुले कड़वे नीम की तरह हैं। वे बॉडी मास इंडेक्स की बातें ऐसे करते हैं जैसे खुदा न खास्ता जीवन कोई गणित का इम्तिहान हो। पर छंगामलपुर का दर्शन स्पष्ट है- कोलेस्ट्रॉल वह ग्रीस है जो आत्मा के पहियों को दुनिया की खुरदरी हकीकत से रगड़ खाने से बचाता है। यहाँ पोषण एक विदेशी बीमारी है जो शायद किसी रास्ता भटके हुए एनजीओ के साथ गाँव में दाखिल हुई होगी। हमारा विश्वास तो लॉन्जिविटी की डीप-फ्राई थ्योरी में है–अगर किसी वस्तु को खौलते हुए तेल में इतना तपाया गया है कि उसमें सीसा भी पिघल जाए,तो वह वस्तु समस्त विकारों से मुक्त होकर मोक्ष के योग्य हो जाती है।

यही कारण है कि जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पधारते हैं, तो उन्हें सलाद परोसना एक अघोषित युद्ध की घोषणा माना जाता है। साहब के सम्मान में जलेबियाँ आती हैं–शुद्ध चीनी की वे जटिल कुंडलियाँ जो हमारी कानूनी पेचीदगियों को भी मात देती हैं। जैसे-जैसे साहब जलेबियाँ गटकते हैं,उनकी ठुड्डियाँ गुणात्मक रूप से बढ़ने लगती हैं। तीसरी जलेबी तक पहुँचते-पहुँचते जब उनकी तीन ठुड्डियाँ चमकने लगती हैं, तो जनता इसे उनकी बौद्धिक गहराई का प्रमाण मान लेती है। गाँव की शाश्वत बुद्धि कहती है कि जो आदमी अपनी कैलोरी गिनता है, उसे कभी गाँव का कोई गुप्त रहस्य नहीं बताना चाहिए,जो अपने पेट के प्रति इतना कंजूस है, वह सरकारी बजट के प्रति कितना क्रूर होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। मोटापा यहाँ अहिंसा का सर्वोच्च शिखर है। एक भारी-भरकम आदमी न तो किसी का पीछा कर सकता है, न किसी से गुत्थमगुत्था हो सकता है; वह बस एक जगह बैठकर दुनिया को अपनी गरिमा से डरा सकता है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

जिला पंचायत सीईओ पर अमर्यादित भाषा के आरोप

डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,हड़ताल की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) विनय अग्रवाल पर बैठक के दौरान अपमानजनक एवं अमर्यादित भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। इस संबंध में संघ ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराया। संघ का कहना है कि 6 फरवरी को जिला पंचायत द्वारा योजनाओं की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में विकासखंड स्तर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। अभियंताओं के अनुसार बैठक के दौरान सीईओ द्वारा तकनीकी सहायक (आवास) आशुतोष शुक्ला को उप अभियंता तपन चक्रेश के संबंध में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए गए। संघ ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी पूर्व की बैठकों में अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। संघ ने इसे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल बताया है।

हड़ताल की चेतावनी : संघ ने कहा है कि यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो जिले के अभियंता काम बंद कर हड़ताल पर जा सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

मनरेगा नियमों के उल्लंघन का भी आरोप : डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मनरेगा अंतर्गत नियुक्त संविदा तकनीकी सहायकों से अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य कराए जाने पर भी आपत्ति जताई है। संघ ने शासन और भारत सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि तकनीकी सहायकों से केवल मनरेगा के कार्य ही कराए जाने चाहिए।

इसके बावजूद जिले की कई जनपद पंचायतों में उप अभियंताओं के कार्य तकनीकी सहायकों को सौंपे जाने का आरोप लगाया गया है।

शासन निर्देशों के पालन की मांग

संघ ने मांग की है कि सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं।

बुकिंग कर मैनपाट घूमने गए बदमाशों ने वापसी के दौरान लूटी स्कॉर्पियो

पुलिस ने देर रात कोरबा के जंगल से वाहन को किया बरामद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगई चौक के पास से बदमाशों ने स्कॉर्पियो लूटकर फरार हो गए थे। 4 बदमाशों ने पहले स्कॉर्पियो बुक कर मैनपाट घुमा, वापस आने के दौरान उल्टी आने की बहाना कर वाहन को रूकवाए और बेल्ट से चालक का गला दबाकर मारपीट करने लगे। इस दौरान जान बचाते हुए चालक वाहन से उतर गया और बदमशों ने वाहन लेकर फरार हो गए। सूचना पर दरिमा पुलिस ने वाहन को कोरबा जंगल से देर रात को बरामद किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के भट्ठी रोड निवासी अंकित सिन्हा का स्कॉर्पियो है। जिसे किराए में चलाता है। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे पुराना बस स्टैंड से पंचर दुकान का संचालक ने अंकित को फोन कर बताया कि चार लोग स्कॉर्पियो बुक कर मैनपाट घुमने जाना चाहते हैं। अंकित स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 15 सीजे 5333 लेकर पुराना बस स्टैंड पहुंचा और चारो अज्ञात व्यक्ति को लेकर मैनपाट गया। वहां घुमाने के बाद सभी को लेकर शाम को वापस लौट रहा था। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगई चौक के पास पहुंचा तो स्कॉर्पियो के पीछे बैठा एक व्यक्ति उल्टी आने की बात कह कर गाड़ी को रोकवाया, इस दौरान एक व्यक्ति अंकित के गले में बेल्ट लगाकर दबाने लगा और अन्य लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। वह डर से गाड़ी से नीचे उतर गया। इसके बाद चारो अज्ञात व्यक्ति ने वाहन को लूटकर वहां से फरार हो गए।

पकड़े जाने के डर से वाहन को जंगल में छोड़ भागे बदमाशा : शाम करीब 7.30 बजे वारदात के बाद अंकित किसी तरह दरिमा थाने पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस विवेचना शुरू कर दी। डीआईजी राजेश अग्रवाल ने जिले के सभी थाने व सीमावर्ती थाने को भी घटना से अवगत कराया और वाहन जांच करने के निर्देश दिए। दरिमा थाना प्रभारी राजेश खलखो ने बताया कि कोरबा पुलिस द्वारा प्वाइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसकी जानकारी होने पर बदमाशों ने कोरबा जंगल में ही वाहन छोडक़र फरार हो गए।

गौ खरीदी बिक्री मामले में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर

-संवाददाता-
बलरामपुर,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के के डीडों चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा 15 नग गाय बछड़ा को क्रूरता पूर्वक हांकते मारते लेजाया जा रहा है, सूचना पर डिंडो चौकी प्रभारी ने मौके पर पुलिस स्टाफ को डिंडो तिराहा भेजकर 4 आरोपीयो को गिरफ्तार कर आरोपी घीरसाय पिता भगवत उम्र 55 वर्ष,राज रूप पिता दिलबर,दोनों ग्राम कोटराही,थाना त्रिकुंडा, जिला बलरामपुर राम प्रसाद पिता शिबू, निरपत पिता लालू, दोनों निवासी ग्राम बरवाही चितमहुराव, जिला बलरामपुर कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर। जानकारी के अनुसार दिनांक 10/02/2026 को 4:30 बजे भोर में मुखबिर से सूचना मिली की वाडरफनगर नगर तरफ से डिडो होते हुए झारखंड 15 बैल गाय बछड़ा को चार लोग हाकते हुए पशुओं के साथ मारपीट कर क्रूरता पूर्वक ले जा रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी डिंडो द्वारा तस्दीक हेतु मौके पर तत्काल पुलिस स्टाफ भेजा गया था जो डिंडो तिराहा में चार लोग 15 मवेशियों को मारपीट करते ला रहे थे जिन्हें रोक कर पूछताछ करने पर अपना नाम घीरसाय पिता भगवत उम्र 55 वर्ष, राज रूप पिता दिलबर, दोनों ग्राम कोटराही राम प्रसाद पिता शिबू, निरपत पिता लालू, दोनों निवासी ग्राम बरवाही चितमहुराव के द्वारा मवेशियों को ले जाते मिले जिससे मवेशी को खरीद बिक्री करने संबंधी नोटिस देकर कागजात पेश करने को कहा गया जो कोई दस्तावेज का होना नहीं बताऐ तथा गांव वाले से भी तस्दीक करने पर इन लोगों के द्वारा मवेशियों को गांव से लेकर झारखंड बाजार में बेचते हैं वहां से बुचड खाना ले जाते हैं जो आरोपियों का कत अपराध धारा पशु परीक्षण अधिनियम का 4, 6 ,10 ,एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(घर) की धारा का अपराध घटित होने से आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे प्रधान आरक्षक संतोष कुमार सिंह आरक्षक शिव भजन पोर्ट शिवनारायण सिंह नंदलाल गोस्वामी राम पुकार तेजू राम रहे।

एसआईआर प्रक्रिया में फार्म-7 को लेकर राजनीतिक विवाद,कांग्रेस ने जताई आपत्ति

1143 मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास का आरोप, जांच की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर शहर की राजनीति में विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से ऑनलाइन फार्म-7 भरकर एक वर्ग विशेष के मतदाताओं के नाम विलोपित कराने की कोशिश की गई है। कांग्रेस की ओर से राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भेजी गई शिकायत में बताया गया है कि शहर में अब तक 1143 ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया गया है, जिनके नाम नियम विरुद्ध तरीके से हटाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस का दावा है कि पूरे जिले में यह संख्या कई हजार तक हो सकती है। शिकायत में भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अंशुल श्रीवास्तव, पार्षद पति विकास गुप्ता, पार्षद प्रत्याशी रहे विशेष केशरवानी, पूर्व पार्षद अवधेश सोनकर सहित डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों के नामों का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि अलग-अलग मतदान केंद्रों के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फार्म-7 भरे गए। कांग्रेस ने कहा कि निर्वाचन नियमों के अनुसार फार्म-7 भरने वाला व्यक्ति उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए, जबकि 99 प्रतिशत मामलों में यह शर्त पूरी नहीं हुई। इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम हटाने की अनुशंसा की गई, उनमें निर्वाचित पार्षद, पूर्व पार्षद, बीएलओ और अन्य शासकीय कार्यालयों में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत लोग भी शामिल हैं, जो अभी भी संबंधित वार्ड में निवासरत हैं।

फार्म निरस्त करने और कार्रवाई की मांग : कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए ज्ञापन में मांग की है कि नियम विरुद्ध भरे गए सभी फार्म-7 तत्काल निरस्त किए जाएं। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देकर फार्म भरने वालों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन सौंपने गए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल, आशीष वर्मा, पार्षद हसन खान, मेराज रंगरेज, शुभम जायसवाल, जीवन यादव, जमील खान, शानू मुखर्जी, अमित सिन्हा, अविनाश कुमार, अंशु सिंह, मिथुन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

निर्वाचन अधिकारी ने जांच का भरोसा दिलाया

इस मामले को लेकर स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं निर्वाचन अधिकारी की ओर से शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाए जाने की बात कही जा रही है।

मुख्यमंत्री साय के मुख्य आतिथ्य में 13 फरवरी को मैनपाट महोत्सव 2026 का होगा भव्य शुभारंभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले के मैनपाट में रोपाखार जलाशय के पास तीनदिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन 13 से 15 फरवरी तक किया जा रहा है। तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित है। शुभारंभ अवसर पर 13 फरवरी को कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल करेंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी, आदिम जाति विकास कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम,लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद श्री चिंतामणी महाराज होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, भरतपुर-सोनहत विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, बैकुण्ठपुर विधायक श्री भईयालाल राजवाड़े, पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय, प्रतापपुर विधायक श्रामती शंकुतला पोर्ते, प्रेमनगर विधायक श्री भूलन सिंह मरावी, सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, गृह निर्माण मण्डल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, राज्य युवा आयोग अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री देव नारायण यादव, नगर निगम अम्बिकापुर सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत सदस्य सुश्री रतनी नाग, जनपद पंचायत अध्यक्ष मैनपाट श्रीमती संतोषी पैकरा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मैनपाट श्री अनिल सिंह, जनपद पंचायत सदस्य मैनपाट श्रीमती प्रीति रजनीश पाण्डे एवं ग्राम पंचायत रोपाखार के सरपंच श्री सुखू राम शामिल होंगे।

पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा माह का भव्य समापन

1100 नागरिकों ने बनवाया लर्निंग लाइसेंस

जागरूकता कार्यों के लिए सम्मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले में 37 वें राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह का समापन समारोह मंगलवार को पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत बसंत, डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल, नगर निगम सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी तथा महापौर मंजूषा भगत उपस्थित रहे। पुलिस मुख्यालय रायपुर के दिशा-निर्देशन में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के पालन के लिए जिलेभर में विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सडक़ सुरक्षा माह के दौरान स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, वाहन परीक्षण, स्कूल बस चालकों-परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान करीब 1100 नागरिकों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाकर लाभ लिया।

सडक़ हादसों में 32 प्रतिशत कमी का दावा

डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि जागरूकता अभियानों, पोस्टर-बैनर, यातायात रथ और परिवहन विभाग के सहयोग से सडक़ दुर्घटनाओं में लगभग 32 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। भविष्य में भी लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

नियम पालन की अपील

महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि यातायात नियमों का पालन स्वयं से शुरू होना चाहिए। नागरिकों की सहभागिता से ही सडक़ दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। कलेक्टर अजीत बसंत ने मैनपाट महोत्सव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा रिंग रोड पर अनाधिकृत पार्किंग रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई की बात कही।

बेहतर कार्य करने वालों का हुआ सम्मान

समापन समारोह में एनसीसी-एनएसएस कैडेट्स, छात्र-छात्राओं, वाहन चालकों, पुलिस मितान, फिट कॉप फिट सिटी सदस्यों सहित 100 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। जरूरतमंदों को हेलमेट वितरित कर दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की गई। कार्यक्रम में पुलिस, परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और नागरिक मौजूद रहे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा का संकल्प सम्मेलन सम्पन्न

एकात्म मानववाद और अंत्योदय के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र पुनर्निर्माण का लिया संकल्प

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं प्रखर राष्ट्रचिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जिला भाजपा कार्यालय में संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य विषय वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक हेमंत नाग तथा वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आभार वक्ता के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्य वक्ता हेमंत नाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, संगठन निर्माण और वैचारिक स्पष्टता का अद्भुत उदाहरण है। अत्यंत साधारण पारिवारिक परिस्थितियों से उठकर उन्होंने भारतीय जनसंघ को वैचारिक आधार प्रदान किया। उन्होंने 'एकात्म मानववाद' के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर आधारित समग्र विकास का मार्ग दिखाया, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक जीवंत इकाई के रूप में देखा गया है। हेमंत नाग ने कहा कि पंडित जी का मानना था कि विकास का केंद्र अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति होना चाहिए। उनका 'अंत्योदय' का विचार आज भी शासन और समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे उनके सिद्धांतों को आत्मसात कर राष्ट्रहित में कार्य करें। सम्मेलन में ललन प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता हमारे प्रेरणास्त्रोत श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का तपस्यापूर्ण जीवन देश की सेवा के लिए आजीवन समर्पित रहा। राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उनकी विचारधारा सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी।

आगे उन्होंने कहा कि पंडित जी ने राजनीति को सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का माध्यम माना। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को जन-जन तक पहुंचाया और संगठन शक्ति को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। आज आवश्यकता है कि हम उनके आदर्शों को व्यवहार में उतारते हुए समाज के हर वर्ग तक पहुंचें और सेवा, समर्पण एवं सुशासन के संकल्प को सशक्त करें। इस अवसर पर आभार वक्ता भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में हमारा दायित्व है कि हम उनके विचारों को केवल स्मरण न करें, बल्कि उन्हें अपने आचरण और कार्यशैली में उतारें।

अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन के पूर्व जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने दीनदयाल चौक पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

असम के विज्ञापन पर कांग्रेस का हमला,संविधान पर हमला बताया

परवेज आलम गांधी बोले...नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज़ आलम गांधी ने असम में सामने आए एक कथित विज्ञापन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि असम में जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, वह केवल एक विज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारतीय संविधान की मूल भावना पर सीधा हमला माना जाना चाहिए। परवेज़ आलम गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेकर बनी सरकार को उसके मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने मांग की कि संबंधित मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता, तो यह संकेत होगा कि नफरत फैलाने वाली गतिविधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने सामाजिक एकता और न्याय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि देश के संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

सामूहिक विवाह में विधायक के सवालों से मचा हड़कंप,आंगनबाड़ी की भूमिका पर उठी नई बहस

क्या तय होती हैं जोड़ियां? सामूहिक विवाह मंच से विधायक के सवालों ने चौंकाया

- गायत्री मंदिर में विवाह, मंच से उठे सवाल-प्रक्रिया पर खड़े हुए नए प्रश्न
- विधायक के तीखे सवालों से घिरा सामूहिक विवाह आयोजन,विभागीय व्यवस्था चर्चा में
- लक्ष्य पूर्ति या सामाजिक योजना? विधायक के सवालों ने बढ़ाई पारदर्शिता की मांग
- सामूहिक विवाह में सब कुछ तय? विधायक के सवालों से सन्न रह गया पंडाल
- आंगनबाड़ी की भूमिका पर उठे प्रश्न,विधायक की पूछताछ से गरमाया माहौल
- विवाह मंच पर सवाल ही सवाल-क्या व्यवस्था पर उठी शंका या सिर्फ जिज्ञासा?

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

कोरिया जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2026 के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम उस समय चर्चा का केंद्र बन गया,जब नगर पटना स्थित गायत्री मंदिर में आयोजित विवाह समारोह के दौरान बैकुंठपुर विधायक ने वर-वधुओं से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए,जिनसे पूरे आयोजन की प्रक्रिया,पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर काम करने वाली व्यवस्था को लेकर नई जिज्ञासाएं खड़ी हो गईं,कार्यक्रम भले ही धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ,लेकिन बैकुण्ठपुर विधायक के सवालों ने वहां मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सामूहिक विवाह योजना केवल सामाजिक सहयोग का माध्यम है या इसके पीछे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो आमजन की जानकारी से परे हैं।

विधायक के सवालों ने चौंकाया,मंच पर छाया सन्नाटा

जानकारी के अनुसार,विवाह स्थल पर पहुंचे बैकुण्ठपुर विधायक ने युवक-युवतियों से सीधे संवाद करने का प्रयास किया,उन्होंने पूछा कि क्या सभी जोड़े आपसी सहमति और पारिवारिक निर्णय से विवाह कर रहे हैं,क्या वे पहले से एक-दूसरे को जानते हैं,और क्या किसी स्तर पर उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या विभागीय व्यवस्था के माध्यम से चयनित किया गया है,इन सवालों के दौरान अधिकांश नवदंपति अपने वैवाहिक अनुष्ठानों और नए जीवन की शुरुआत में व्यस्त नजर आए और किसी ने स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी, विधायक ने बार-बार प्रश्न दोहराए,लेकिन जवाब न मिलने पर खुद ही शांत हो गए, हालांकि उनके सवालों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया।

क्या लक्ष्य पूर्ति का दबाव बन रहा है चर्चा का विषय?- विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठने लगा कि कहीं सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में संख्या पूरी करने का दबाव तो नहीं होता, कुछ लोगों का कहना है कि योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित होने के कारण निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं पर ज्यादा प्रयास करने का दबाव रहता है, जिससे चयन प्रक्रिया को लेकर शंकाएं पैदा हो सकती हैं, हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी तक किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत या जांच सामने नहीं आई है, विभागीय सूत्रों का कहना है कि योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है और सभी जोड़ों की पात्रता तय प्रक्रिया के अनुसार ही जांची जाती है।

क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना?- प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह में सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, इसके अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है, योजना के तहत वधु को लगभग 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया जाता है, इसके अलावा गृहस्थी से जुड़ी सामग्री भी दी जाती है तथा प्रति जोड़ी भोजन, आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए अलग से राशि खर्च की जाती है। कार्यक्रम में वर-वधु पक्ष के परिजनों को भी निर्धारित संख्या में शामिल होने की अनुमति रहती है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है?- जानकारों के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भूमिका मुख्यतः जागरूकता फैलाने और पात्र परिवारों को योजना की जानकारी देने तक सीमित होती है। वे गांव स्तर पर परिवारों को समझाती हैं कि सामूहिक विवाह कम खर्च में सम्मानजनक विकल्प हो सकता है, लेकिन विधायक के सवालों के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या उनकी भूमिका केवल प्रेरणा तक सीमित है या चयन प्रक्रिया में भी प्रभावी होती है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अंतिम चयन प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही होता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल प्रारंभिक संपर्क का माध्यम होती हैं।

भ्रष्टाचार की चर्चा या सिर्फ राजनीतिक सवाल?- कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों ने यह भी चर्चा शुरू कर दी कि क्या निचले स्तर पर किसी प्रकार की अनियमितता या दबाव की स्थिति बनती है।

हालांकि फिलहाल यह केवल अटकलों तक सीमित है और किसी भी तरह के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी सामाजिक योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा और खुली जानकारी जरूरी होती है, ताकि किसी भी तरह की शंका स्वतः समाप्त हो सके।

विधायक के सवालों से विभाग पर बढ़ा दबाव

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधायक द्वारा सार्वजनिक मंच से पूछे गए सवाल सीधे तौर पर विभागीय कार्यप्रणाली पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता पर केंद्रित थे, इससे विभाग पर यह दबाव जरूर बढ़ा है कि वह योजना की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट तरीके से सामने रखे, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न रहे।

सवाल ज्यादा,जवाब कम

नगर पटना में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न जरूर हुआ, लेकिन विधायक द्वारा उठाए गए प्रश्न अब भी चर्चा में हैं। क्या यह केवल एक राजनीतिक सवाल था या फिर व्यवस्था की गहराई में छिपे किसी मुद्दे की ओर इशारा– यह आने वाला समय ही तय करेगा, फिलहाल इतना तय है कि सामाजिक योजनाओं की सफलता केवल आयोजन से नहीं, बल्कि उनकी पारदर्शिता और लोगों के विश्वास से तय होती है, विधायक भले ही मंच पर मौन हो गए हों, लेकिन उनके सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं और जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आधी रात जयनगर थाने पहुंचे डीआईजी/एसएसपी,औचक निरीक्षण में गश्ती व्यवस्था परखते हुए जवानों को किया प्रोत्साहित

-संवाददाता-
सूरजपुर,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों की सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है, इसी क्रम में 9-10 फरवरी 2026 की दरम्यानी रात डीआईजी/एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर अचानक जयनगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण कर रात्रि गश्त, थाना रिकॉर्ड और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। आधी रात वरिष्ठ अधिकारियों को अपने बीच पाकर थाना स्टाफ और गश्ती दल तुरंत अलर्ट मोड में नजर आए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी/एसएसपी ने थाना के रिकॉर्ड अपडेट, नाइट ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत रात्रि गश्त विवरण,निगरानी व्यवस्था और क्षेत्र के गुंडा-बदमाशों की सूची की समीक्षा की। रिकॉर्ड व्यवस्थित पाए जाने पर उन्होंने 'गुड' कहकर टीम की सराहना की और कहा कि रात के समय थाना पहुंचने वाले पीड़ितों की हरसंभव मदद करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखें, थाना निरीक्षण के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जयनगर थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग रात्रि गश्त प्वाइंट का भी औचक निरीक्षण किया। यहां तैनात अधिकारी और जवान सतर्क एवं सक्रिय मिले, जिस पर उन्होंने संतोष जताते हुए संवेदनशीलता के साथ गश्त करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि रात्रि गश्त का मुख्य उद्देश्य अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत करना है, इस दौरान डीआईजी/एसएसपी ने जवानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। उन्होंने ड्यूटी के दौरान सजगता,नियमित डॉक्यूमेंटेशन और पेशेवर व्यवहार बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस की सक्रियता ही अपराधियों में भय और आम लोगों में विश्वास पैदा करती है,वरिष्ठ अधिकारियों के इस अचानक निरीक्षण से पुलिस महकमे में सक्रियता और अनुशासन का संदेश साफ तौर पर दिखाई दिया।

परीक्षा नहीं,सीखना बने जीवन का लक्ष्य : प्राभाकर उपाध्याय

-संवाददाता-
सूरजपुर 11 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

परीक्षा के बढ़ते दबाव और विद्यार्थियों में तनाव को देखते हुए शिक्षा जगत से सकारात्मक संदेश सामने आया है, सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर एवं साधु राम विद्या मंदिर के प्राचार्य प्राभाकर उपाध्याय ने कहा है कि परीक्षाएँ जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि परीक्षा को बोझ नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखें। उन्होंने बताया कि आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में केवल अंक ही सफलता की गारंटी नहीं हैं, संचार कौशल, रचनात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान और तकनीकी दक्षता जैसे जीवन कौशल विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। नई शिक्षा नीति और सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली भी अब रटने की प्रवृत्ति से आगे बढ़कर अनुभवात्मक शिक्षण और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दे रही है, प्राभाकर उपाध्याय ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की तुलना दूसरों से न करें और उन पर अधिक अंक लाने का दबाव न बनाएं।

MVU तुरंत ही मौके पर पहुंच कर,बछिया का आपरेशन करके उसके गोबर करने का रास्ता बनाया

-संवाददाता-
सूरजपुर,11 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

रामपुर गांव से(पशुपालक रजमेन),जो कि सूरजपुर ब्लॉक,जिला सूरजपुर के अंतर्गत आता है के द्वारा, 1962 टोल फ्री नंबर के द्वारा एक इमरजेंसी फोन,MVU ब्लॉक सूरजपुर को आया,जिसमें यह बताया गया कि एक गाय ने 3 दिन पहले एक बछिया को जन्म दिया था, जिसमें जन्म से ही गुदाद्वार/Rectum/गोबर करने का रास्ता नहीं था। जिसका ईलाज केवल सर्जरी था। पशुपालक बहुत परेशान थे,उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उन्हें चलित पशु चिकित्सा इकाई के बारे में पड़ोस ने बताया और उन्होंने 1962 में फोन करके अपना केस रजिस्टर्ड कराया। जैसे ही इमरजेंसी केस का कॉल आया,सूरजपुर ब्लॉक के MVU तुरंत ही मौके पर पहुंच कर,उनका आपरेशन करके उसके गोबर करने का रास्ता बनाया। और गोबर आसानी से अब पास हो रहा है, इससे पशुपालक में अत्यन्त हर्ष है और उन्होंने संपूर्ण MVU team ko ऐसे ही नेक काम करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस ऑपरेशन में डॉ. प्रशांत कुमार उपाध्याय, Paravet(AVFO)- संदीप साहू, Pilot - अरुण पाण्डेय उपस्थित थे।

पुलिस की नजर में कोयला बीनना भी अपराध? ग्रामीणों ने नगर सैनिक पर लगाया वसूली का आरोप,कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
सूरजपुर/भैयाथान,11 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

क्षेत्र के भास्करपारा कोयला खदान से जुड़े विवाद ने अब प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। खदान के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने बसदेई चौकी में पदस्थ एक नगर सैनिक सहित अन्य स्टॉफ पर कथित अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर,सूरजपुर को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि भास्करपारा कोयला खदान में प्रकाश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। खनन, लोडिंग और परिवहन के दौरान अक्सर कोयला सड़क किनारे या आसपास गिर जाता है,जिसे प्रभावित ग्राम पंचायतों के लोग घरेलू उपयोग के लिए एकत्र कर ले जाते हैं। आरोप है कि इसी दौरान बसदेई चौकी में पदस्थ नगर सैनिक अनिल विश्वकर्मा और उनके साथ मौजूद अन्य स्टॉफ द्वारा ग्रामीणों से पैसों की मांग की जाती है।

कार्रवाई की धमकी देने का आरोप- ग्रामीणों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि यदि पैसे नहीं दिए जाते तो पुलिस कार्रवाई करने, चौकी ले जाने और केस दर्ज करने की धमकी दी जाती है।

इससे क्षेत्र के गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल घरेलू जरूरत के लिए गिरे हुए कोयले को उठाते हैं, बावजूद इसके उन्हें परेशान किया जा रहा है।

कलेक्टर से जांच और स्थानांतरण की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कथित वसूली में शामिल नगर सैनिक अनिल विश्वकर्मा एवं अन्य स्टॉफ के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, साथ ही उन्हें बसदेई चौकी से हटाने की भी मांग उठाई गई है,ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और लोग प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं,हालांकि,इस संबंध में पुलिस विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, अब देखना होगा कि जिला प्रशासन ग्रामीणों की शिकायतों पर क्या कदम उठाता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।

न्यायालय तहसीलदार सोनहत, जिला कोरिया,छत्तीसगढ़

राजस्व प्रकरण क्रमांक/ब-121/2025-26

ईश्तहार

ग्राम नटवाही

सर्वसाधारण ग्रामीण जानता ग्राम नटवाही प ह न 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल सोनहत तहसील सोनहत जिला कोरिया (छग.) को सूचित किया जाता है आवेदक रूप चंद्र गुप्ता आ. गुलाब चंद गुप्ता जाति वैश्य निवासी ग्राम नटवाही तहसील सोनहत जिला कोरिया छ.ग. के द्वारा अपने पुत्री निर्मला गुप्ता के लिए केन्द्र सरकार के अंतर्गत लोक पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति हेतु / शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारत 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु संलग्न छायाप्रति दस्तावेज कक्षा 12 वी, अंकसूची, शपथ पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, के साथ EWSs प्रमाण पत्र हेतु निवेदन किया गया है।

अतः किसी कोई हितबद्ध पक्षकार को EWSs के संबंध मे आपत्ति / दावा प्रस्तुत कैरना चाहते है तो दिनांक 18.02.2026 तक अपना आपत्ति/ दावा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति / दावा पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।

उक्त ईश्तहार आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है

(सील) तहसीलदार
सोनहत

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला- सूरजपुर(छ.ग.)

सार्वजनिक उद्घोषणा/ ईश्तहार

क्रमांक/1943/वाचक-2/2025
सूरजपुर दिनांक 11/02/2026

सर्व साधारण ग्रामवासी/नगरवासी नगर सूरजपुर प0ह0न0 .... तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो. शमसेर इराकी पिता स्व. शमीम इराकी जाति मुसलमान निवासी ग्राम सुरजपुर तहसील सूरजपुर ने अपने पिता स्व. साकिर अली मृत्यु तिथि 20/12/2017 स्थान सूरजपुर के मृत्यु पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/आक्षेप हो तो वे स्वय अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 25/02/ 2026 दिन बुधबार को उपस्थित होकर दावा /आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा / आपत्ति / आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(सील) तहसीलदार
सूरजपुर,छ0ग0

सती त्याग के प्रसंग से नम हुईं आँखें...

शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन मिनी स्टेडियम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

संशय छोड़ो, श्रद्धा अपनाओ-आचार्य विनय कांत त्रिपाठी की वाणी से सराबोर हुआ मिनी स्टेडियम

शिव-पार्वती की झांकी पर पुष्प वर्षा, तीसरे दिन भक्ति में सराबोर हुआ पूरा पंडाल

संवाददाता

कोरिया/सोनहत, 11 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। स्थानीय मिनी स्टेडियम में आयोजित भव्य शिव महापुराण कथा का तीसरा दिन श्रद्धा, भावनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा, जैसे ही विख्यात कथावाचक आचार्य विनय कांत त्रिपाठी ने माता सती के त्याग और भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया, पूरा पंडाल भक्ति के रंग में रंग गया, हजारों श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण गूंजता रहा, कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं, उन्होंने व्यासपीठ का पूजन कर क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की तथा श्रद्धालुओं के बीच बैठकर कथा का श्रवण किया। माता सती के प्रसंग ने किया भावुक, नम हुईं आँखें- तीसरे दिन की कथा का मुख्य केंद्र माता सती का त्याग और भगवान शिव के प्रति उनका अटूट समर्पण रहा। आचार्य विनय कांत त्रिपाठी ने बताया कि संशय किस तरह भक्ति को कमजोर कर देता है, उन्होंने विस्तार से समझाया कि माता सती द्वारा भगवान श्रीराम की परीक्षा लेने का प्रसंग केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है-जहां संदेह आता है, वहां दुख और विछोह निश्चित होता है, कथा के दौरान कई श्रद्धालु भावुक होकर आँसू पोंछते नजर आए। पंडाल में ऐसा आध्यात्मिक माहौल बना कि लोग मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनते रहे।

विधायक रेणुका सिंह की सादगीपूर्ण उपस्थिति

कार्यक्रम में पहुंचीं विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है, उन्होंने आम श्रद्धालुओं के बीच बैठकर कथा सुनी और आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी सादगीपूर्ण उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया।

अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु-आचार्य की सीख

कथावाचक ने नारद मोह का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि जब ज्ञान और तपस्या पर अहंकार हावी हो जाता है, तो ईश्वर स्वयं माया के माध्यम से उसे तोड़ देते हैं, उन्होंने कहा कि भगवान शिव को पाने के लिए भक्ति में सरलता और समर्पण जरूरी है, उन्होंने भगवान शिव के लिंग स्वरूप के प्राकट्य और ब्रह्मा-विष्णु को दिए गए दायित्वों का भी वर्णन किया, जिससे श्रोता गहरे आध्यात्मिक चिंतन में डूब गए।

श्रद्धा में संदेह का स्थान नहीं

आचार्य विनय कांत त्रिपाठी ने कहा...श्रद्धा का मार्ग विश्वास का मार्ग है। जहां संशय होता है, वहां पतन तय है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ और सती दाह के प्रसंग पर कथा जब चरम पर पहुंची, तो पूरा पंडाल शांत और भावनाओं से भरा दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने ध्यानपूर्वक कथा सुनी और कई लोग ध्यानमग्न होकर भगवान शिव का स्मरण करते नजर आए।

शिव-पार्वती की झांकी ने बदला माहौल

कथा के दौरान प्रस्तुत भगवान शिव और माता पार्वती की सजीव झांकी ने पूरे आयोजन को उत्सव में बदल दिया, कलाकारों द्वारा प्रस्तुत यह झांकी इतनी आकर्षक रही कि पंडाल में बैठे श्रद्धालु कैलाश धाम का अनुभव करने लगे, जैसे ही झांकी मंच पर आई, विधायक रेणुका सिंह सहित आयोजन समिति और भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, भजनों की मधुर धुन और जयघोषों के बीच पूरा मिनी स्टेडियम आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा।

मिनी स्टेडियम छोटा पड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों से उमड़ी भीड़

तीसरे दिन कथा श्रवण के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, मिनी स्टेडियम का विशाल मैदान भी श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे छोटा नजर आने लगा, आयोजन समिति द्वारा बैठने, शीतल जल और सुगम दर्शन की बेहतर व्यवस्था की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो।

भंडारे में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

कथा के समापन के बाद आयोजित भंडारे में भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हुए भजनों पर झूमते नजर आए। पूरा वातावरण हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंजता रहा और आध्यात्मिक उत्साह देर शाम तक बना रहा।

बदमाशों के खिलाफ कोरबा पुलिस ने की कार्यवाही

-संवाददाता-

कोरबा, 11 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। कोरबा जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में कोरबा पुलिस द्वारा जिले भर में प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। इस दौरान कोरबा पुलिस द्वारा रात्रि के समय सार्वजनिक स्थलों पर बेवजह घूमने, अड्डेबाजी करने एवं झुंड में एकत्रित होकर संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 128 बीएनएसएस के तहत कुल 20 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन बना विवाद का केंद्र

पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग पर लगाए गंभीर आरोप

-संवाददाता-

एमसीबी, 11 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 10 फरवरी 2026 को खड़गवां में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम अब सियासी और प्रशासनिक विवादों के केंद्र में आ गया है। पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने जिला प्रशासन स्ख्क और महिला एवं बाल विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयोजन को अव्यवस्थित, असुविधापूर्ण और संभावित अनियमितताओं से घिरा बताया है। उनके आरोपों के बाद योजना के क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ईमानदार कलेक्टर के रहते ऐसे फैसले कैसे?

पूर्व विधायक ने कहा कि जब जिले में एक ईमानदार कलेक्टर पदस्थ हैं, तब नियमों को दरकिनार कर जिला स्तरीय कार्यक्रम को जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के बजाय खड़गवां में आयोजित करना समझ से परे है।

ब्लॉक स्तर पर आयोजन न करने की साजिश का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर कार्यक्रम को विकासखंड स्तर पर न कर कई पात्र परिवारों को योजना से वंचित करने की कोशिश की जा रही है।

यह जनता की योजना है, मनमर्जी नहीं चलेगी...

पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जनता की योजना है और इसमें राजनीतिकरण, मनमानी या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से पारदर्शिता और जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने की मांग की।

कड़े सवाल

आखिर जिम्मेदार कौन?

पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने प्रशासन से सवाल करते हुए कहा **इस हादसे का जिम्मेदार कौन है?** जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उनके मुताबिक यह घटना योजनाओं के अव्यवस्थित क्रियान्वयन और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है।

पिछले वर्ष के कथित भ्रष्टाचार का भी जिक्र

गुलाब कमरों ने पिछले वर्ष MCB जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के दौरान कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए कहा कि उस समय उच्चस्तरीय शिकायतें की गई थीं, लेकिन अब तक न जांच हुई और न ही किसी अधिकारी पर कार्रवाई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस बार भी वही स्थिति दोहराई जा रही है।

योजना के मूल उद्देश्य से भटका प्रशासन : गुलाब कमरों

पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कहा...कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब, वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान आयोजन में इस मूल भावना को नजरअंदाज किया गया है, उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम को विकासखंड स्तर पर आयोजित करने के बजाय एक ही स्थान पर केंद्रित कर दिया गया, जिससे कई जरूरतमंद परिवारों के लिए योजना तक पहुंच मुश्किल हो गई है, उनका कहना है कि यदि आयोजन ब्लॉक स्तर पर होता तो ग्रामीणों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती और अधिक संख्या में पात्र परिवार लाभान्वित हो सकते थे।

दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ अन्याय का आरोप

गुलाब कमरों ने जनकपुर और कोटाडोल जैसे वनांचल क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के साधनविहीन परिवारों के लिए खड़गवां तक पहुंचना बेहद कठिन है, उन्होंने इसे प्रशासनिक असंवेदनशीलता बताते हुए कहा कि गरीब परिवारों को जोखिम भरी लंबी यात्रा के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो योजना की भावना के विपरीत है।

बस दुर्घटना में 13 ग्रामीण घायल, प्रशासन पर जिम्मेदारी का आरोप

कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनकपुर से चनवारीडाड़खड़गवां जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 13 ग्रामीण घायल हो गए, घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक ने चौकी प्रभारी नागपुर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर घायलों के बेहतर उपचार की मांग की, उन्होंने कहा कि यदि आयोजन विकासखंड स्तर पर किया गया होता, तो ग्रामीणों को इतनी दूर यात्रा नहीं करनी पड़ती और यह हादसा टल सकता था, उन्होंने दुर्घटना के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।

जांच, बेहतर इलाज और मुआवजे की मांग

उन्होंने मांग की कि बस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सभी घायलों को बेहतर इलाज और उचित मुआवजा दिया जाए तथा भविष्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसे आयोजनों को अनिवार्य रूप से विकासखंड स्तर पर आयोजित किया जाए, ताकि सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके।

न्यायालय तहसीलदार, अम्बिकापुर जिला -सरगुजा छ0ग0

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विष्णु सोनपाकर आ0 कृष्ण राम निवासी सकालो थाना अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर ने कराया है कि आवेदक के (दादाजी) स्व. हवल साथ आ0. स्व. शिवबालक की दिनांक 01/04/2023 को स्थान निवास में हुई है।
आवेदक के मृत्यु उपरांत मृत्यु का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।
उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा 1

आज दिनांक 17/11//2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर, सरगुजा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं बलवन्तराम, ग्राम-सलका, पोस्ट-प्रेमनगर, तहसील-प्रेमनगर, पुलिस थाना- प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छ0ग0) है। यह कि मेरा सैन्य संख्या 15176168F, हवलदार के पद पर कार्यरत था । मैं 23/06/2006 को भारतीय थल सेना ज्वाइनिंग किया था और दिनांक-30/04/2025 को भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूं। मेरे उक्त भारतीय थल सेना के सेवा पुस्तिका (सर्विस रिकार्ड) में मेरे माता का नाम केवलावति (KEWLAWATI) तथा जन्म तिथि- 01/07/1961 अंकित है तथा मेरे पिता का नाम रामचलित्तर (RAM-CHALITTAR) जन्म तिथि 01/7/1956 अंकित है जो त्रुटीपूर्ण है।
मेरी माता का सही व वास्तविक नाम कलावती (KALAVATI) तथा जन्म तिथि - 01/03/1963 है और मेरे पिता जी का सही नाम (RAM CHARITAR) तथा जन्म तिथि - 01/01/1955 है जो कि उनके आधार कार्ड में भी अंकित है। मैं अपने भारतीय थल सेना के सेवा पुस्तिका (सर्विस रिकार्ड) में अपने माता-पिता का सही व वास्तविक नाम तथा जन्मतिथि सुधार कराना चाहता हूं। जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। जिस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र निष्पादित है जो सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता
बलवन्तराम, ग्राम-सलका

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर -2 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0-202601021700034/ /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राधेश्याम अग्रवाल आ0 किशोरी लाल अग्रवाल, निवासी रायपुर (छ0ग0) की ओर से मुख्तारआम शैलेन्द्र कुमार सोनी आ0 रामलखन सोनी, निवासी ब्रम्हरोड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा (छ0ग0) द्वारा अपने ग्राम सरगवां स्थित व्यपवर्तित भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 199136.43 वर्गफीट भूमि में से 23620 वर्गफीट अनावेदिका ज्योति जायसवाल आ0 नन्दू प्रसाद जायसवाल, निवासी बौरीपारा, अल्का इण्डस्ट्रीज के पास अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ0ग0) व अन्य 09 को कुल रू0 2,36,20,000/- (दो करोड़ छत्तीस लाख बीस हजार रूपये) में विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है । उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 20/02/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, छ0ग0

क्र0/1087 / स्था0-01/2026 — सूरजपुर दिनांक 04/02/2026

शासकीय वाहनों की खुली निलामी हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर छ0ग0 के अंतर्गत निष्प्रयोजित शासकीय वाहनों की खुली निलामी द्वारा विक्रय किया जाना है प्रस्तावित है। निम्नानुसार शासकीय वाहनों की खुली निलामी दिनांक 19/02/2026 दिन गुरूवार को समय 12.00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - सूरजपुर छ0ग0 के कार्यालय परिसर में किया जायेगा । इच्छुक खरीदार कार्यालयीन समय में आकर नीलामी की जाने वाली वाहनों का अवलोकन कर सकते है ।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	स्थान जहां वाहन उलब्ध है।	रिमार्क
1.	CG 02 6976	टाटा विगर	सामु.स्वा.केन्द्र रामानुजनगर	
2.	CG 02 1721	स्वाराज माजदा	सामु.स्वा.केन्द्र प्रेमनगर	
3.	Tomp228/mh/14	गामा फोर्स	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
4.	CG 02 5811	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
5.	CG 02 5826	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
6.	CG 02 1723	स्वाराज माजदा	सामु.स्वा.केन्द्र प्रतापपुर	
7.	CG 02 5692	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
8.	CG 02 5595	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
9.	CG 02 5793	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
10	CG 02 5702	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
11	CG 02 6874	बुलोरो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
12	CG 02 5827	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
13	CG 02 5804	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
14	CG 02 5792	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	
15	CG 02 5825	टाटा सुमो	जिला चिकित्सालय सूरजपुर	

नियम व शर्तें -
1. प्रत्येक खरीदार को बोली लगाने के पूर्व रूपये 5000.00/- (पाँच हजार रूपये) प्रतिभूति जमा करना अनिवार्य होगा। जिन खरीददारों की बोली स्वीकार नही होगी उन्हे जमा की गई प्रतिभूति राशि वापस कर दी जावगी ।
2. खरीददार की उच्चतम बोली स्वीकार किये जाने पर सम्पूर्ण राशि एक सप्ताह के भीतर जमा कर निलामी की गई वाहन कार्यालय से ले जाना होगा ।
3. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। 4. वाहन जिस स्थिति में है और जहां है उसी स्थिति में निलामी की होगी ।
5. यह जानकारी एनआईसी सूरजपुर के वेबसाईट www.surajpur.gov.in में उपलब्ध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- सूरजपुर छ0ग0

जी नंबर-252606578/4

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः, 202601020700087

विषय:-ब-121 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन्:-2025-26

सुभाषनगर प.ह.न.00017 [(हे0)]
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - रमेश राय,
अनावेदक पक्षकार -छ0ग0शासन,

ईश्तहार

आवेदक रमेश राय आ0 फूलचंद राय, निवासी ग्राम सुभाषनगर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सुभाषनगर स्थित खसरा नंबर 204/12 रकबा 0.100 हे0 तथा खसरा नंबर 204 / 13 रकबा 0.010 हे0 भूमि के नकशा में त्रुटि हो गया है। आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि के नक्शा में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27.02.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14/01/2026 को जारी किया जाता है।

सील — उमेश्वर सिंह बाज, तहसीलदार, अंबिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर -2 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण दिलेश्वर आ0 स्व0 अमृत व अन्य 03 निवासी ग्राम सरगंवा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम सरगंवा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 291, 292, 441, 569, 644, 658 रकबा 0.7800, 1. 2100, 0.4900, 0.2100, 0.4100, 1.7000 हे0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 18/02/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा

आज दिनांक 23/01 /2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर -2 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक साहेब आ. स्व. लोधी, व अन्य 12 जाति पनिका, निवासी ग्राम करम्हा, तहसील अम्बिकापुर के द्वारा माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश अम्बिकापुर जिला सरगुजा के व्य. अपील क्र. 58 ए / 2012 में पारित निर्णय/आज्ञाप्ति दिनांक 12/03/2015 के परिपालन में ग्राम करम्हा स्थित भूमि खसरा नंबर 128 / 2 रकबा 0.450 हे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण का नाम दर्ज किये जाने तथा वाद भूमि का कब्जा अनावेदक अश्विनी कुमार सिंह आ. एम. एम. सिंह से आवेदकगण को दिलवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/02 / 2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 04/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर -2 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सरजीत मण्डल आ0 स्व0 तारक मण्डल निवासी ग्राम नेहरूनगर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदकगण के स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम नेहरूनगर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 281 रकबा 0.32 हे0 का पट्टा आवेदकगण के पिता को प्राप्त हुआ है। किन्तु रकबा 0.32 के स्थान पर त्रुटिवश रकबा 0.60 हे0 दर्ज हो गया है। उक्त भूमि में से रकबा 0.43 आरे भूमि को आवेदकगण के द्वारा विक्रय भी कर दिया गया है। वर्तमान रिकार्ड में खसरा क्रमांक 281/1 रकबा 0.2100 हे0 भूमि दर्ज है। आवेदक के द्वारा रकबा 0.2100 हे0 के स्थान पर रकबा 0.320 हे0 दर्ज किये जाने हेतु आवेदनपत्र माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/02/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 05/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

क्या खाली कुर्सियों की गूंज रायपुर तक जाएगी?

कार्रवाई की आहट या सिर्फ चर्चा?

खाली कुर्सियां गूंजती रहीं,रायपुर रहा शांत-सहज स्वभाव ने थामे रखा मामला?

मंच पर टिप्पणी, गलियारों में खामोशी-घूघरा विवाद क्यों नहीं हुआ गर्म?

घूघरा की चूक पर सियासत शांत,क्या सीएम और उनकी धर्मपत्नी की सादगी बनी ढाल?

खाली कुर्सियां बनीं हेडलाइन, लेकिन रायपुर में सन्नाटा क्यों?

तेवर सख्त होते तो क्या बदल जाती तस्वीर? घूघरा मामला अब भी ठंडा

मंच पर व्यंग्य, सत्ता में मौन-घूघरा कार्यक्रम की गूंज दब गई क्या?

खामोश नेतृत्व या प्रशासन की राहत? घूघरा की चूक पर नहीं गिरी गाज

टिप्पणी बड़ी थी, प्रतिक्रिया छोटी-रायपुर के गलियारों में क्यों पसरा सन्नाटा?

जो अंत तक टिका रहता है...घूघरा के मंच से निकली एक लाइन और प्रशासनिक 'शो मैनेजमेंट' की खुल गई परतें...

-जिला प्रतिनिधि-

कोरिया,11 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड अंतर्गत ग्राम घूघरा में आयोजित जंगल कैफे उद्घाटन कार्यक्रम अब विकास से ज्यादा प्रशासनिक चूक और 'मैनेजमेंट की कहानी'बन चुका है,मंच सजा था,बैनर चमक रहे थे, स्वागत में कोई कमी नहीं थी-लेकिन जैसे ही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी उदबोधन देने खड़ी हुई,सामने खाली कुर्सियों की कतारें जैसे पूरे आयोजन का सच बयान करने लगीं,और फिर मंच से निकली एक पंक्ति-जो अंत तक टिका रहता है वही कुछ पाता है-ने प्रशासनिक तैयारी पर ऐसा व्यंग्य किया कि पूरा कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया।

बता की घूघरा के मंच पर जो दृश्य दिखा,उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या इस पूरे मामले की जवाबदेही तय होगी या फिर यह भी बाकी सरकारी आयोजनों की तरह फाइलों के बीच दबकर रह जाएगा,क्योंकि जिस कार्यक्रम में यह चूक हुई, उसमें जिला कलेक्टर स्वयं मौजूद थीं और पूरी व्यवस्थाओं की कमान भी प्रशासन के हाथ में ही मानी जा रही थी, ऐसे में स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि अगर संख्याबल और प्रोटोकॉल की इतनी बड़ी चूक हुई,तो जिम्मेदारी तय होना स्वाभाविक है, प्रशासनिक जानकारों की मानें तो किसी भी वीआईपी विजिट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और विशेष तौर पर कलेक्टर की होती है। मंच,सुरक्षा, समय प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण-ये सभी बिंदु सीधे कलेक्टर की निगरानी में आते हैं। ऐसे में जब मुख्य अतिथि के सामने खाली कुर्सियां नजर आएं और मंच से ही इस पर टिप्पणी हो जाए, तो इसे केवल संयोग कहकर नजर अंदाज करना आसान नहीं होता,हालांकि अभी तक शासन स्तर से किसी औपचारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि यदि रायपुर तक रिपोर्ट पहुंची तो स्पष्टीकरण मांगा जाना तय माना जा सकता है।

घुघरा में 'जंगल कैफे' का शुभारंभ,बसन्तोत्सव में शामिल हुई मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय-पर्यटन,संस्कृति और सियासत का दिखा संगम

पत्रकारों के सवालों पर अधूरे विद्युतीकरण और पंडो जनजाति के जाति प्रमाणपत्र मुद्दे को सरकार तक पहुँचाने का भरोसा, विधायक की गैरमौजूदगी और 'सुपर ...' वाले तंज से बढ़ी राजनीतिक चर्चा

बसन्तोत्सव में शामिल होकर किया 'जंगल कैफे' का उद्घाटन

पर्यटन, संस्कृति और राजनीति-तीनों का मिला संगम

स्थानीय विधायक की गैरमौजूदगी बनी चर्चा का विषय

'लखपति दीदी' की दिशा में बढ़ रहीं महिलाएं: देवेंद्र तिवारी

'हमर पहुनी आइन हे' भईयालाल राजवाड़े का भावुक स्वागत

घटती घटना | सरगुजा,सूरजपुर कोरिया समाचार | अम्बिकापुर, रविवार 08 फरवरी 2026 | 4

वसंतोत्सव या प्रशासनिक स्क्रिप्ट? जंगल कैफे उद्घाटन ने खड़े किए नए सवाल
सरकारी पैसा,फीता 'विशेष अतिथि' के हाथ-कोरिया में नई परंपरा की शुरुआत?

अजब आयोजन, गजब प्रोटोकॉल! घुघरा कार्यक्रम पर सियासी और प्रशासनिक बहस तेज

- वसंतोत्सव के बहाने उद्घाटन राजनीति? प्रशासन की भूमिका पर उठे बड़े सवाल
- मंच पर बसन्त,पर्दे के पीछे प्रशासन-कोरिया का कार्यक्रम बना चर्चा का केंद्र
- फीता किसका,फैसला किसका? घुघरा में 'जंगल कैफे' से ज्यादा प्रोटोकॉल चर्चा में
- सवालों के बीच वसंतोत्सव- क्या छत्तीसगढ़ में बदल रही है उद्घाटन की परंपरा?
- अजब जिला, गजब उद्घाटन! प्रशासन पीछे, चर्चा आगे
- जंगल कैफे उद्घाटन पर सवालः बुलावा किसने भेजा, आयोजन किसने साधा?
- महिला समूह की ताकत या प्रशासन की रणनीति-वसन्तोत्सव बना राजनीतिक पहेली
- किसके इशारे पर आया काफिला? जंगल कैफे उद्घाटन के पीछे की कहानी चर्चा में

सोशल मीडिया बना आईना...

कार्यक्रम खत्म होते ही खाली कुर्सियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पूर्व विधायक की पोस्ट ने भी संख्याबल पर सवाल उठाकर मामले को और हवा दे दी,लोगों के बीच यह चर्चा है कि अगर हर पंचायत से महिलाओं को लाने का लक्ष्य तय था, तो आखिर भीड़ अंत तक क्यों नहीं टिक सकी? क्या इंतजार ज्यादा लंबा था या कार्यक्रम में आकर्षण कम?

क्या गिरेगी कार्रवाई की गाज?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है-क्या इस चूक की जिम्मेदारी तय होगी? प्रशासनिक जानकारों के मुताबिक, केवल भीड़ कम होने से तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होना तय नहीं होता। लेकिन अगर शासन इसे प्रोटोकॉल की गंभीर चूक मानता है,तो स्पष्टीकरण या समीक्षा संभव है, यानी अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह घटना प्रशासनिक फाइलों में नोट जरूर हो सकती है।

निजी आयोजन का नाम,सरकारी व्यवस्था का काम

कागजों में कार्यक्रम को महिला समूह संगठन का बताया गया,लेकिन मंच से लेकर भीड़ जुटाने तक हर व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण में दिखाई दी,स्थानीय चर्चाओं में इसे जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया शो बताया जा रहा है,जहां उद्देश्य सिर्फ जंगल कैफे का उदघाटन नहीं,बल्कि जिले की उपलब्धियों को प्रदेश नेतृत्व तक दिखाना था,कलेक्टर की सक्रियता,स्वागत से लेकर विदाई तक की भागदौड़ और मंच संचालन की पूरी कमान प्रशासन के हाथ में होने से यह सवाल उठना लाजिमी हो गया-अगर सब कुछ प्रशासन का था,तो फिर भीड़ प्रबंधन में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?

सहज स्वभाव ने थामे रखी सियासी गर्मी?

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही अपने शांत और सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं,शायद यही वजह है कि घूघरा के कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें और मंच से निकली टिप्पणी के बावजूद मामला अभी तक रायपुर के गलियारों में ज्यादा गरमाता नजर नहीं आ रहा,स्थानीय विश्लेषकों का कहना है कि यदि किसी सख्त तेवर वाले नेतृत्व के दौर में ऐसी स्थिति बनती,तो प्रशासनिक स्तर पर तत्काल जवाबदेही तय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था,हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी नाराजगी या कार्रवाई का संकेत सामने नहीं आया है,लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की संयमित प्रतिक्रिया ने फिलहाल माहौल को शांत बनाए रखा है। व्यंग्य यह है कि मंच पर खाली कुर्सियां चर्चा में जरूर रहीं, पर सत्ता के गलियारों में सन्नाटा उतना ही कायम दिखा-मानो मामला देखो और आगे बढ़ो की नीति पर छोड़ दिया गया हो।

संख्याबल का गणित और खाली कुर्सियों की सच्चाई

सूत्र बताते हैं कि कार्यक्रम में भीड़ सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई थी, महिला स्व-सहायता समूहों से महिलाओं को लाने के निर्देश भी दिए गए थे,शुरुआत में भीड़ ठीक-ठाक रही, लेकिन मुख्य अतिथि के आगमन में देरी और लंबा इंतजार ग्रामीणों के धैर्य पर भारी पड़ गया,धीरे-धीरे कुर्सियां खाली होती गई और जब भाषण का वक्त आया तो मंच के सामने का दृश्य प्रशासनिक 'प्लानिंग' पर सवाल खड़ा कर गया, व्यंग्य यही है कि सरकारी आयोजनों में अक्सर कुर्सियां कम पड़ जाती हैं, लेकिन यहां कुर्सियां ज्यादा और लोग कम पड़ गए।

कलेक्टर की मौजूदगी और जिम्मेदारी का सवाल

कार्यक्रम में कलेक्टर स्वयं मौजूद थीं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह पूरी चूक केवल आयोजक संस्था की थी या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है? प्रशासनिक परंपरा में वीआईपी विजिट की व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होती है,अगर मुख्य अतिथि के सामने खाली कुर्सियां दिखें और मंच से इस पर टिप्पणी हो जाए,तो इसे सिर्फ संयोग कहकर टालना आसान नहीं होता, हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन चर्चाओं में यह जरूर कहा जा रहा है कि यदि शासन स्तर पर संज्ञान लिया गया तो जवाबदेही तय हो सकती है।

उपलब्धि दिखाने की जल्दबाजी या रणनीतिक आयोजन?

जंगल कैफे को डीएमएफ मद से तैयार किया गया है और इसे जिले की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया,आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह आयोजन विकास से ज्यादा छवि निर्माण का मंच था? स्वागत और मंच सजावट में प्रशासन की पूरी ताकत दिखी, लेकिन समय प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण में वही मजबूती नजर नहीं आई,ऐसा लगा मानो पूरा कार्यक्रम 'फोटो फ्रेम' के लिए बनाया गया था-जहां कैमरे के सामने सब कुछ परफेक्ट दिखे, लेकिन भाषण के वक्त वास्तविकता सामने आ जाए।

डीएमएफ मद पर भी उठे तंज

घूघरा का जंगल कैफे डीएमएफ मद से बना है, जिसे पर्यटन और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर प्रचारित किया गया। मगर जिले में पहले से डीएमएफ मद के उपयोग को लेकर उठते सवालों के बीच इस उद्घाटन को कुछ लोग 'क्लीन चिट अभियान' भी बता रहे हैं,आलोचकों का कहना है कि महिला समूहों का कंधा इस्तेमाल हुआ और निशाना प्रशासनिक उपलब्धि दिखाने का रहा। हालांकि प्रशासन की ओर से इसे विकास की पहल बताया गया है।

व्यंग्यात्मक सच-मंच सजा था,पर दर्शक गायब

घूघरा का यह आयोजन एक अजीब विरोधाभास छोड़ गया-मंच पर विकास की बातें थीं,लेकिन सामने विकास सुनने वाले लोग नहीं थे। स्वागत में गर्मजोशी थी,पर भाषण के वक्त खालीपन भी उतना ही साफ दिखा, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का वाक्य अब इस आयोजन की पहचान बन चुका है–जो अंत तक टिका रहता है वही कुछ पाता है। और शायद इस बार यह लाइन सिर्फ जनता के लिए नहीं,बल्कि प्रशासन के लिए भी एक संदेश बन गई-कि सरकारी शो तभी सफल होता है जब जनता अंत तक साथ रहे,वरना खाली कुर्सियां ही सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाती हैं।

आयोजनों में भीड़ दिखाओ की परंपरा तो पुरानी...लेकिन भीड़ टिकाओ की जिम्मेदारी नजरअंदाज कैसे...

व्यंग्य यह है कि जिस आयोजन को उपलब्धियों का प्रदर्शन बनाकर पेश किया गया,वही अब प्रशासनिक समीक्षा का कारण बनता दिख रहा है,सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ समय प्रबंधन की चूक थी, या फिर भीड़ जुटाने की पूरी रणनीति ही कागजी साबित हो गई? पंचायतों को जिम्मेदारी,महिला समूहों को लक्ष्य और प्रशासन की सक्रियता-सब कुछ होने के बावजूद मंच के सामने खालीपन आखिर किसकी विफलता है? राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि बड़े आयोजनों में भीड़ दिखाओ की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन भीड़ टिकाओ की जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है,घूघरा का कार्यक्रम भी शायद इसी जल्दबाजी का शिकार बन गया-उद्घाटन तक सब ठीक,लेकिन भाषण के वक्त व्यवस्था की असल तस्वीर सामने आ गई,फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने इस पर मंच के बाद कोई औपचारिक नाराजगी जताई या नहीं,लेकिन उनका एक वाक्य ही प्रशासन के लिए आईना बन गया,अब देखना यह होगा कि शासन इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक साधारण आयोजन की कमजोरी मानता है या इसे प्रोटोकॉल की गंभीर चूक समझकर जिम्मेदारी तय करता है,क्योंकि सवाल सिर्फ खाली कुर्सियों का नहीं है-सवाल उस व्यवस्था का है, जहां मंच पर सब कुछ चमकदार दिखता है,लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब माइक चालू होता है और सामने जनता मौजूद रहती है...या नहीं रहती।

70 के दशक का बच्चा...

अमिताभ बच्चन के स्टारडम पर पड़ा भारी

नन्हे स्टार के पास थीं बिग बी से ज्यादा फिल्में!

बजट अमिताभ का बड़ा था,कद अमिताभ का बड़ा था,लेकिन फिल्मों की लिस्ट मास्टर राजू की बड़ी थी। जी हां,आज हम आपको 70 के दशक उस नन्हे स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके पास अमिताभ बच्चन से ज्यादा काम था। खुद हाल ही में उस स्टार ने इसका खुलासा किया है। हिंदी सिनेमा में 70 और 80 के दशक का वो दौर था,जब महानायक अमिताभ बच्चन अपनी एंग्री यंग मैन वाली इमेज का सिक्का चलता था। उस दौर में बिग बी मानो सिनेमा की गद्दी पर राज कर रहे थे। इसी बीच एक ऐसा बच्चा आया,जो फिल्मों का मास्टर बन गया।

इस छोटे पैकेट ने मानो महानायक के स्टारडम को भी चुनैती दे डाली थी। अगर हम आपसे कहें कि इस बच्चे के पास उस दौर में बड़े-बड़े एक्टर्स से ज्यादा फिल्मों के ऑफर थे,तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? पर जनाब हकीकत तो यही है। हाल ही में खुद इस एक्टर ने इस बारे में खुलासा किया है। तो जानते हैं उसी की कहानी...

अमिताभ पर भारी पड़ा मास्टर राजू का स्टारडम?

दरअसल ये हम नहीं बल्कि किसी और ने कहा

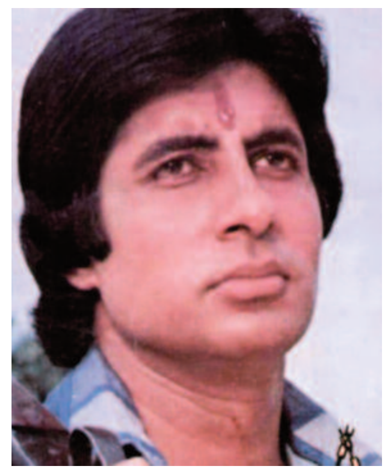

है और जिन्होंने कहा है उनका नाम है मास्टर राजू यानि एक्टर राजू श्रेष्ठ । वही राजू श्रेष्ठ जिन्होंने 70-80 के दशक में कई फिल्मों बाल कलाकर के तौर पर काम किया है। उनका असली नाम फहीम अजनी है जिन्हें अपने स्टेज नाम मास्टर राजू और राजू श्रेष्ठ से जाना जाता है। हाल ही में मास्टर राजू ने बताया कि कैसे एक दौर था,जब उन्हें बड़े-बड़े सितारों से भी ज्यादा फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे थे। सिद्धार्थ कनन से बातचीत में इसका खुलासा किया है। राजू श्रेष्ठ ने बताया कि,

अमित जी वक्त के बहुत पाबंद हैं, और मैं ये कैसे कहूं पर उस दौर में उनके पास मुझसे कम काम था? ये कहते हुए भी मुझे हंसी आ रही है। वो वक्त पर आ जाते थे और उनके क्लोज-अप शॉट्स पहले ले लिए जाते थे। फिर, जब मैं आता था, तो उनसे साइड में बैठने के लिए कहा जाता था क्योंकि मेरे शॉट्स को प्राथमिकता दी जाती थी,क्योंकि मुझे तीन घंटे में निकलना होता था। उस दौरान अमित जी बस इंतज़ार करते रहते थे। जब मेरे शॉट्स पूरे हो जाते थे,तब जाकर उनके बचे हुए क्लोज-अप लिए जाते थे।

जब बिग बी को मास्टर राजू की मां ने डांटा इस बातचीत में मास्टर राजू ने बताया कि एक बार उनकी मां ने भी अमिताभ बच्चन को डांट लगा दी थी। मास्टर राजू ने बताया कि, फरार के सेट पर,मेरी मां ने अमित जी को डांटा था। एक सीन में,वो अपने हाथ पर लगा एक घाव दिखा रहे थे और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वहीं लंच चल रहा था और हम खाना खा रहे थे। मेरी मां ने कहा, प्लीज इसे ढक लीजिए,यहां मक्खियां आ रही हैं और हम खाना खा रहे हैं। इसके साथ ही इस बातचीत में मास्टर राजू ने बताया कि सिर्फ अमिताभ बच्चन ही उस दौर में ऐसे एक्टर थे,जो वक्त पर फिल्म के सेट पर आते थे। बाकी कई कलाकार ऐसे थे, जो हमेशा लेट आते थे। आपको बता दें कि,200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मास्टर राजू ने मात्र 3 साल की उम्र से अपना करियर शुरू किया था।

15 अगस्त 1966 को जन्मे मास्टर राजू की पहली फिल्म शर्त (1969) में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। सबसे ज्यादा लाइमलाइट मास्टर राजू को फिल्म चितचोर से मिली,जिसके लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था। उन्होंने राजेश खन्ना,अमिताभ बच्चन से लेकर कई स्टार्स के साथ काम किया। इसके साथ ही वो कई टीवी शोज में भी नजर आए हैं।

विनोद खन्ना की बर्बादी का वो धुआं

एक दिन में पी जाते थे 40 से 80 सिगरेट, मौत से पहले ऐसी थी हालत

विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना ने खुलासा किया है कि अभिनेता को ब्लैडर कैंसर से पहले 2001 में फेफड़ों का कैंसर हुआ था,जिसका कारण अत्यधिक धूम्रपान था। आध्यात्मिक सलाह और जर्मनी यात्रा के बाद यह कैंसर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वहीं 2010 में जब उन्हें ब्लैडर कैंसर हुआ,तो डॉक्टरों ने बताया था कि उनके जीवित रहने की बहुत कम संभावना थी।

विनोद खन्ना का नाम बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर्स में गिना जाता है। उनकी छवि पर्दे पर एक आइडल एक्टर की थी। उन्होंने अपनी स्माइल और लुक्स से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। हालांकि फिल्मी पर्दे पर दमदार स्क्रीन प्रीजेंस होने के बावजूद विनोद खन्ना अपनी हेल्थ को लेकर पर्सनल लाइफ में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे।

एक्टर के निधन के इतने साल बाद अब पत्नी कविता खन्ना ने उन अनछुए पहलुओं को टच करने की कोशिश की है जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। कविता ने बताया कि ब्लैडर कैंसर से पहले विनोद खन्ना को एक और भयंकर बीमारी हो गई थी।

पहले हुआ था फेफड़ों का कैंसर

विनोद खन्ना का साल 2017 में 70 साल की आयु में ब्लैडर कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया था। हालांकि, हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में, कविता ने खुलासा किया कि उन्हें सबसे पहले 2001 में लंग्स के कैंसर का पता चला था। इसका मूल कारण एक्टर का बहुत ज्यादा धूम्रपान करना था।

कविता ने बताया कि विनोद खन्ना हैवी स्मोकर थे और एक दिन में 40 से 80 सिगरेट पी लेते थे। इस वजह से उनके फेफड़ों में कुछ धब्बे आ गए थे। स्पेशलिस्ट ने उस समय सलाह दी थी कि उनके लंग्स से वो हिस्सा हटाया जा सकता है।

एक्टर ने बीमारी को रखा सीक्रेट

हालांकि एक्टर ने बीमारी को सीक्रेट रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने आध्यात्मिक सलाह भी ली। सर्जरी को टालने के लिए डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने कुछ समय ऋषिकेश में बिताया। इसके बाद दोनों जर्मनी चले गए। यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसपर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने कहा-बाद में जब हम जर्मनी गए तो एक शाम, विनोद को कंधे के पास बहुत तेज दर्द हुआ। वो दो दिन तक दर्द में तड़पते रहे थे। उनके टेस्ट हुए और रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कैंसर का कोई नामों निशान नहीं था।

जिंदा रहने के थे बहुत कम चांस

इसके बाद साल 2010 में उन्हें ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट हुआ। उस समय उनकी हालत ज्यादा खराब थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर वो एलोपैथी का सही से इलाज करवाते हैं,तो भी दो साल बाद उनके जिंदा रहने की संभावना केवल 25प्रतिशत थी। इस दौरान विनोद खन्ना ने अलग फैसला लिया। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और अपनी बॉडी को और टॉर्चर नहीं करना चाहता। उन्होंने आश्रम में पंचकर्म थेरेपी ली और दो साल के अंदर स्कैन में पता चला कि कैंसर गायब हो गया था। हमने अमेरिका में स्कैन करवाए थे और रिपोर्ट्स में कैंसर नहीं आया। हालांकि आखिरी में उनका निधन ब्लैडर कैंसर से हुआ।

औरतों को छेड़ रहे थे दो आदमी,कॉन्सर्ट रोकर फेमस सिंगर ने लिया एक्शन,लात मारकर कराया बाहर,फैंस बोले...रियल लाइफ धुरंधर

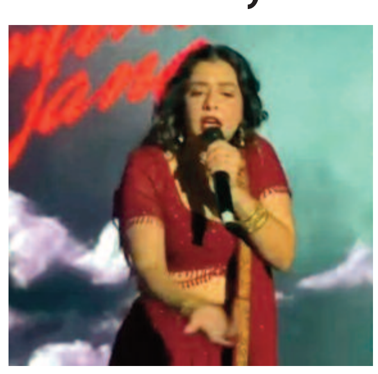

सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट का एक वीडियो काफी चर्चा में आ गया है। सिंगर इस वीडियो में एक्शन में नजर आ रही हैं। वीडियो देखने के बाद लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की पॉपुलर सिंगर जैस्मिन सैंडलस सिर्फ अपनी दमदार आवाज के लिए ही नहीं,बल्कि अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। 'तारास','यार ना मिले','इल्लीगल वेपन 2.0' और हाल ही में फिल्म धुरंधर के ट्रैक 'शरारत' जैसी हिट्स देने वाली जैस्मिन ने हाल ही में दिल्ली में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान ऐसा कदम उठाया, जिसने उन्हें फैंस की नजरों में और ऊंचा कर दिया। दिल्ली में आयोजित एक लाइव शो के दौरान जैस्मिन ने अचानक अपनी परफॉर्मेंस बीच में रोक दी। वजह थी ऑडियंस में मौजूद कुछ आदमी थे, जो महिलाओं को परेशान कर रहे थे।

जैस्मिन ने लिया एक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जैस्मिन को साफ शब्दों में सिक्योरिटी से कहते सुना गया,सिक्योरिटी,क्या आप प्लीज इन दो लोगों को लात माकर बाहर करे सकते हैं? कुड़ियां नू तंग कर रहे हैं। मैं तब तक नहीं गाऊंगी जब तक लड़कियां सेफ महसूस नहीं करेंगी। मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दृढ़ता थी। न कोई ड्रामा,न चिल्लाना, बस एक सख्त और साफ स्टैंड। यह पल दर्शाता है कि मंच पर खड़ी एक कलाकार सिर्फ एंटरटेनर नहीं,बल्कि जिम्मेदार शख्सियत भी होती है। जैस्मिन का यह कदम तुरंत चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर सराहना की।

खेल समाचार

ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हराया

जम्पा और एलिस ने 4-4 विकेट झटके स्टोयनिस ने 45 रन बनाए

कोलंबो,11 फरवरी 2026। ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली जीत हासिल कर ली है। टीम ने 14 वें मैच में आयरलैंड को 67 रनों से हराया। बुधवार को कोलंबो में खेले गए ग्रूप-बी के इस मैच में कंगारुओं ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी।

कंगारुओं ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाबी पारी में आयरलैंड ने 16.5 ओवर में 9 विकेट पर 115 रन ही बना सकी। नाथन एलिस और एडम जम्पा ने 4-4 विकेट झटके। एक विकेट मैथ्यू कुहनेमन को मिला। कप्तान पॉल स्टर्लिंग पहली बॉल पर रिटायर

हर्ट हो गए हैं। वे बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। जॉर्ज डॉकरेल ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। लोरकन टकर ने 24 रन का योगदान दिया। शेष बैटर्स खास प्रदर्शन नहीं कर सके।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्कस स्टोयनिस ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। जोश इंग्लिस और मैट रैनशॉ ने 37-37 रन बनाए।

आयरलैंड की ओर से मार्क अडायर ने 2 विकेट झटके। मैथ्यू हम्फ्रीज, जॉर्ज डॉकरेल और हैरी टेक्टर ने एक-एक विकेट लिए।

प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया:- ट्रैविस हेड (कप्तान),जोश इंग्लिस (विकेटकीपर),कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, कॉनोली,ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोयनिस,नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट,मैथ्यू कुहनेमन, एडम जम्पा।

आयरलैंड:- पॉल स्टर्लिंग (कप्तान),रॉस अडायर,हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर),कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज,जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी,मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी,मैथ्यू हम्फ्रीज।

टोटेनहम ने थॉमस फ्रैंक को नौ महीने बाद किया बर्खास्त

लंदन,11 फरवरी 2026। टोटेनहम हॉटस्पर ने मैनेजर थॉमस फ्रैंक को नौ महीने बाद निकाल दिया है। प्रीमियर लीग क्लब ने बुधवार को यह जानकारी दी। खराब नतीजों की वजह से नॉर्थ लंदन का यह क्लब रेलीगेशन ज़ोन से पांच पॉइंट ऊपर आ गया था। फ्रैंक पर दबाव बढ़ रहा था, और न्यूकैसल यूनाइटेड से 2-1 से घरेलू हार के बाद, उनकी टीम 26 मैचों में 29 पॉइंट के साथ 16वें स्थान पर थी और रेलीगेशन

ज़ोन में जाने के लिए तैयार दिख रही थी। स्पर्स ने एक बयान में कहा, थॉमस को जून 2025 तक के लिए अपॉइंट किया गया था,और हमारा पक्का इरादा है कि हम उन्हें भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए ज़रूरी समय और सपोर्ट दें। हालांकि,नतीजों और परफॉर्मेंस की वजह से, बोर्ड ने यह नतीजा निकाला है कि सीज़न के इस समय बदलाव ज़रूरी है। फ्रैंक,जो 2018 में ब्रेंटफ़ोर्ड में शामिल हुए थे और उन्हें एक टॉप-फ़्लाइट क्लब में प्रमोशन दिलाया था,पिछले सीज़न के यूरोपा लीग विनर टोटेनहम में उन्हीं तरीकों को दोहराने में संघर्ष कर रहे हैं। न्यूकैसल यूनाइटेड से मिली हार के बाद, 52 साल के फ्रैंक मुश्किल में लग रहे थे,यह लीग कैंपेन का उनका 11वां मैच था। सपोर्टर्स ने अपनी भावनाओं के बारे में कोई शक नहीं छोड़ा,क्लब के स्टेडियम में उनका मज़ाक उड़ाया और फ्रैंक पर तुम्हें सुबह नौकरी से निकाला जा रहा है के नारे लगाए। यह इस सीज़न में टोटेनहम की प्रीमियर लीग में सातवीं होम हार थी, और उन्होंने अपने फैंस के सामने अपने 13 लीग गेम में से सिर्फ़ दो जीते हैं।

साउथ अफ्रीका ने डबल सुपर-ओवर थ्रिलर में अफगानिस्तान के डर से जीत हासिल की

अहमदाबाद,11 फरवरी 2026। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ग्रूप डी के एक रोमांचक मैच में, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच आईसीसीमेन्स टी 20 वर्ल्ड कप 2026 में एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। दो ज़बरदस्त इनिंग के बाद मैच डबल सुपर ओवर में गया, जिसके बाद प्रोटियाज़ ने आखिरकार जीत हासिल की। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया क्योंकि टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की उम्मीद कर रही थी। सुबह के हालात ने बॉलर्स को कुछ मदद दी, और अफगानिस्तान ने इसका पूरा फायदा उठाया, पहले तीन ओवरों में साउथ अफ्रीकी बैट्समैन को कंट्रोल में रखा। फजलहक फारूकी ने पहला विकेट लिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम को मिड-ऑफ पर एक चालाक धीमी गेंद पर कैच आउट किया। हालांकि,क्विंटन डी कॉक और रयान रिकलटन के बीच ज़बरदस्त पार्टनरशिप की वजह से गेम जल्द ही साउथ अफ्रीका के पक्ष में हो गया। बाएं हाथ की इस जोड़ी ने अफगान बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दीं, सिर्फ 61 गेंदों पर 116 रन बनाए। डी कॉक ने शानदार पुल शॉट से अपनी फिफ्टी पूरी की,41 गेंदों पर 59 रन बनाए, जबकि रिकलटन ने शानदार

प्रदर्शन करते हुए सिर्फ़ 28 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें चार छक्के और पांच चौके शामिल थे।

राशिद ने तीन गेंदों के अंदर डी कॉक और रिकलटन दोनों को आउट करके कुछ देर के लिए रनों का बहाव रोक दिया,लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस (23) और डेविड मिलर (नाबाद 20) की छोटी-छोटी पारियों ने साउथ अफ्रीका को 187/6 का मुश्किल स्कोर बनाने में मदद की। लक्ष्य का पीछा करते हुए, अफ़गानिस्तान ने रहमानुल्लाह गुरबाज़ के ज़ोरदार प्रदर्शन के साथ शानदार शुरुआत की। ओपनर ने दो चौके और तीन छक्के मारे, जिससे टीम सिर्फ़ चार ओवर में 50 रन तक पहुँच गई। साउथ अफ्रीका ने तीन तेज़ विकेट लेकर वापसी की, जिसमें लुंगी एनगिडी ने इब्राहिम ज़द्रान को आउट किया और गुलबदीन नैब को आउट किया, जबकि कगिसो रबाडा ने सेदिकुल्लाह अटल को आउट किया, जिससे अफ़गानिस्तान का स्कोर 51/0 से 52/3 हो गया।

गुरबाज़ ने अपना अटैक जारी रखा, 26 गेंदों में ज़बरदस्त फिफ्टी बनाई, जिसमें सात छक्के और चार चौके शामिल थे। 10 ओवर तक, अफ़गानिस्तान का स्कोर 93/3 था, जिससे प्रोटियाज़ पर प्रेशर बना हुआ था। जॉर्ज लिंडे ने आखिरकार गुरबाज़ की ज़बरदस्त पारी का अंत किया, लेकिन अज़मतुल्लाह उमरज़ई (22) और राशिद खान (20) ने मोमेंटम बनाए रखा। मुकाबला आखिरी ओवर तक आ गया, जिसमें अफ़गानिस्तान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। कगिसो रबाडा के ओवर की शुरुआत खराब रही, एक नो-बॉल और एक वाइड, जिससे अफ़गानिस्तान 187 रन तक पहुँच पाया, लेकिन एक ज़रूरी रन-आउट के कारण एक ड्रामाटिक सुपर ओवर हुआ।

अभिषेक और वरुण शीर्ष बल्लेबाज और गेंदबाज,सिकंदर रजा नंबर 1 ऑलराउंडर बने

नई दिल्ली,11 फरवरी 2026। आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर बने हुए हैं, वहीं वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजों की सूची में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा टी20 फॉर्मेट में नंबर वन ऑलराउंडर बन गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा पहले,इंग्लैंड के फिल साल्ट दूसरे,पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे,इंग्लैंड के जोस बटलर चौथे और भारत के तिलक वर्मा पांचवें स्थान पर हैं। श्रीलंका के पाथुम निसंका छठे स्थान पर हैं। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव सातवें, न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट आठवें, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नौवें और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श दसवें स्थान पर हैं।

साहिबजादा फरहान को यूएसए के खिलाफ खेली गई 73 रन की पारी का जोरदार फायदा हुआ है। इसी पारी की बदौलत फरहान 4 स्थान की छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। गेंदबाजों की

रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती

पहले, पाकिस्तान के अबरार अहमद दूसरे,अफगानिस्तान के राशिद खान तीसरे,इंग्लैंड के आदिल रशीद चौथे,श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा पांचवें,न्यूजीलैंड के जैकब डफी छठे,पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज सातवें, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान आठवें, ऑस्ट्रेलिया के एडम जांपा नौवें और अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान दसवें स्थान पर हैं।

टी20 के शीर्ष ऑलराउंडर्स की सूची में पाकिस्तान के सईम अयूब को पीछे छोड़ते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। अयूब दूसरे स्थान पर हैं। भारत के हार्दिक पांड्या तीसरे, वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज चौथे, पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज पांचवें, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरे छठे, वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड सातवें, अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई आठवें, अफगानिस्तान के मोहम्मब नबी नौवें और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा दसवें स्थान पर हैं।

डी कॉक ने टी 20 वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा

साऊथ अफ्रीका,11 फरवरी 2026। क्विंटन डी कॉक टी 20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले साउथ अफ़्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं।इससे पहले, एबी डी विलियर्स टॉप पर थे। डी कॉक अब विलियर्स को पीछे छोड़कर टॉप पर आ गए हैं।

टी 20 वर्ल्ड कप के 13वें मैच में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ़्रीका ने 187/6 का स्कोर बनाया।

इस मैच में साउथ अफ़्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक 59 रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ ही,वह टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ़्रीकी खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं। डी कॉक ने एबी डी विलियर्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर टॉप पर जगह बना ली है।

टी 20 वर्ल्‌ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ़्रीका के खिलाड़ी 1. क्विंटन डी कॉक - 737* रन 2. एबी डिविलियर्स - 717 रन 3. जेपी डुमिनी - 568 रन 4. डेविड मिलर - 462* रन 5. एडेन मार्करम - 448 रन*

CMYK

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला...होली से पहले किसानों को एकमुश्त मिलेगा धान का पैसा

रायपुर,11 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के हित समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च,2026 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है,जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी।

सांसद बृजमोहन ने बजट 2026-27 को बताया आत्मविश्वास का बजट

बोले-गरीब,किसान,और महिलाओं के सशक्तिकरण का रोडमैप,विकसित भारत का संकल्प मजबूत

रायपुर,11 फरवरी 2026। रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा में इसे 'आत्मविश्वास का बजट' बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हुए कहा... कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। सांसद ने कहा कि बीते ग्यारह वर्षों में देश ने तेज़ी से विकास किया है और वैश्विक पहचान बनाई है। इस बजट के जरिए भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा,'अब भारत रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और थमेगा नहीं।'छत्तीसगढ़ के विकास पर भी उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि 'भारत विस्तार एआई मिशन' के तहत राज्य के किसानों को छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्नत कृषि तकनीक सिखाई जाएगी। धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के समय 1310 रुपये मिलते थे, जबकि आज मोदी सरकार 2369 रुपये और छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये में खरीदी कर किसानों को लाभ मिला।

सांसद ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में बदलाव जिक्र किया : सांसद ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में हुई क्रांति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गति कांग्रेस के 12 किमी प्रतिदिन की तुलना में अब 33 किमी प्रतिदिन है,जबकि रेलवे ट्रैक पहले 6.4 किमी प्रतिवर्ष बिछते थे,अब लक्ष्य 100 किमी प्रतिवर्ष है। दानकुनी-सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भुवनेश्वर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर छत्तीसगढ़ को औद्योगिक लाभ देंगे। औद्योगिक और शैक्षणिक विकास पर सांसद ने कहा...कि बजट में रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। शिक्षा में 42,100 करोड़ रुपये और 15,000 नए स्कूल,5,000 कॉलेज बनाए जाएंगे। इन संस्थानों को अब अनुसंधान की प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित किया जाएगा। युवाओं और महिलाओं के लिए भी राहत है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा और चिकित्सा ऋण पर ब्याज दर 5% से घटाकर 2% किया गया है।हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनने से महिला सशक्तिकरण को गति मिलेगी।

हाईकोर्ट के नियुक्ति निरस्त करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

66 उप अभियंताओं को मिली राहत...

रायपुर,11 फरवरी 2026। ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा की वर्ष 2011 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट द्वारा 66 उप अभियंताओं (सिविल) की नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध बताते हुए रद्द किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने निरस्त की थी 66 उप अभियंताओं की नियुक्तियां

दरअसल,इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ता रवि तिवारी ने अधिवक्ता शाल्विक तिवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 फरवरी 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने भर्ती को अवैध करार देते हुए 66 उप अभियंताओं की नियुक्तियां निरस्त कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों के पास कट-ऑफ तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य था, जबकि कई चयनित अभ्यर्थियों ने आवश्यक डिग्री या डिप्लोमा बाद में प्राप्त किया। ऐसे में उनकी नियुक्तियां प्रारंभ से ही अवैध मानी गईं। कोर्ट ने यह भी पाया कि 275 पदों के लिए जारी विज्ञापन के बावजूद उससे अधिक पदों पर नियुक्तियां की गईं, जो सेवा कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। सुनवाई के दौरान नियुक्त उप अभियंताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे करीब 14 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इसलिए उनके मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। हालांकि,हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा था कि लंबी सेवा अवधि किसी अवैध नियुक्ति को वैध नहीं बना सकती। इसके बाद कोर्ट ने क्वो वारंटो का रिट जारी करते हुए नियुक्तियां रद्द कर दी थीं।

हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती,सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए प्रभावित कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली का रुख किया। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार,11 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य को नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश पारित किया है। यह प्रकरण लगभग 60 शासकीय कर्मचारियों की सामूहिक सेवा-समाप्ति से संबंधित है, जिन्हें प्रारंभिक रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में उप अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त किया गया था।

भारतमाला मुआवजा घोटाला...फरार तहसीलदार-नायब तहसीलदार गिरफ्तार

भूमाफिया-पटवारी और अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार किए थे कूटरचित राजस्व अभिलेख

रायपुर,11 फरवरी 2026। भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा घोटाले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में शशिकांत कुर्रे (तत्कालीन तहसीलदार, अभनपुर) और लखेश्वर प्रसाद किरण (तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा) शामिल हैं। इन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है।

जांच के अनुसार,रायपुर-विशाखापट्नम और दुर्ग-बायपास भारतमाला सड़क निर्माण परियोजना के दौरान पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा। आरोप है कि,उन्होंने अपने अधीनस्थ पटवारी,राजस्व निरीक्षक,भूमाफिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर कूटरचित राजस्व अभिलेख तैयार कराए। इन दस्तावेजों के आधार पर प्रभावित भू-स्वामियों को वास्तविक मुआवजा राशि से कई गुना अधिक भुगतान कराया गया। जिससे शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हुई। भारत-माला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण मामले में 43 करोड़ का घोटाला हुआ है। जमीन को टुकड़ों में बांटकर एनएचएआई को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

बताया गया है कि,दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी,जिसे निरस्त कर दिया गया था। इससे पहले विशेष न्यायालय से इनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा जारी की थी। विशेष न्यायालय रायपुर में आरोपियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के लिए भी प्रकरण विचाराधीन है।

एसडीएम,पटवारी और भू-माफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर घोटाले को अंजाम दिया। शशिकांत और निर्भय पर जांच रिपोर्ट तैयार होने के 6 महीने बाद कार्रवाई हुई थी। निर्भय कुमार साहू सहित 5 अधिकारी-कर्मचारियों पर 43 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा राशि की गड़बड़ी का आरोप है।

जमीन को टुकड़ों में बांटा,80 नए नाम चढ़ाए...

राजस्व विभाग के मुताबिक,मुआवजा करीब 29.5 करोड़ का होता है। अभनपुर के ग्राम नायकबांधा और उरला में भू-माफिया ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे टुकड़ों में काटकर 159 खसरे में बांट दिया। मुआवजा के लिए 80 नए नाम रिकॉर्ड में चढ़ा दिए गए। इससे 559 मीटर जमीन की कीमत करीब 29.5 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई। अभनपुर बेल्ट में 9.38 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ मुआवजा राशि निर्धारित की गई। जिसमें से 246 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं 78 करोड़ रुपए का भुगतान अभी रोक दिया गया है।

क्या है भारत माला परियोजना ?

भारत माला परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, जिसके तहत करीब 26 हजार किलोमीटर आर्थिक कॉरिडोर विकसित किए जाने हैं। यह कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल,नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ेंगे। देश के अधिकांश फ्रेट ट्रैफिक को इन्हीं मार्गों से ले जाने की योजना है। रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर इसी परियोजना का अहम हिस्सा है।

खाकी पर दाग...जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई,हेरोइन बेचते आरक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार

रायपुर,11 फरवरी 2026। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सूखे नशे के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में रायपुर में पदस्थ एक आरक्षक को अवैध मादक पदार्थ चिट्टा (हेरोइन) की बिक्री करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान आरक्षक हिमांशु बर्मन (34 वर्ष), पिता चैतुराम बर्मन, निवासी ग्राम कुण्डा, जिला कबीरधाम, हाल पता जनता कॉलोनी, पुलिस लाइन रायपुर के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक की झिल्ली में रखा लगभग 1 ग्राम चिट्टा, जिसकी अनुमानित कीमत 8 हजार रुपये बताई जा रही है,बरामद किया गया। बताया गया कि पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप कुमार पटेल के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) राहुल देव शर्मा के निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल और सहायक पुलिस आयुक्त इशु अग्रवाल के नेतृत्व में थाना टिकरापारा और आजाद चौक की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।

फेयरवेल-पार्टी और स्कूल फंक्शन में स्टंटबाजी पर लगेगी रोक

रायपुर,11 फरवरी 2026। स्कूलों में विदाई समारोह और दूसरे आयोजनों में स्टूडेंट्स के जोखिम भरे स्टंट्स पर रोक लगाने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने लोक शिक्षण संचालनालय,सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी करने की अनुशंसा की है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 एवं 15 के तहत आयोग ने अनुशंसा की है कि यदि विदाई समारोह या अन्य आयोजन बच्चों की ओर से किए जा रहे हों,तो इसकी पूर्व सूचना शाला प्रबंधन को देना अनिवार्य हो। ऐसे आयोजनों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किया जाए और समारोह शिक्षकों की निगरानी में गरिमामय तरीके से आयोजित हों। शाला प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रकार के जोखिम भरे करतब न हों।

नक्सल ऑपरेशन में अदम्य वीरता दिखाने वाले जवानों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट सख्त,डीजीपी को दो माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश

बिलासपुर,11 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहसिक भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन (असामान्य पदोन्नति) के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता जवानों के लंबित प्रतिनिधित्व पर कानून के अनुसार दो माह के भीतर निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू ने (दीपक कुमार नायक व अन्य बनाम राज्य शासन) में पारित किया।

यह है पूरा मामला : याचिकाकर्ता दीपक कुमार नायक, अग्नु राम कोर्राम और संगीत भास्कर, ये तीनों पुलिस जवान कांकेर जिले में पदस्थ हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे 15 एवं 16 अप्रैल 2024 को बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन का हिस्सा थे। यह ऑपरेशन कांकेर जिले के कालपर-हापाटोला-छेटेबेठिया क्षेत्र में हुआ, जहां 40-50 सशस्त्र माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में 29 सशस्त्र नक्सली मारे गए, जिनमें 15 पुरुष एवं 14 महिलाएं शामिल थीं। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद भी जब्त किया गया।

केवल 54 पुलिसकर्मियों को मिला प्रमोशन

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इस सफल ऑपरेशन में कुल 187 पुलिसकर्मी शामिल थे, लेकिन शासन द्वारा केवल 54 पुलिसकर्मियों को ही पुलिस विनियम 70(क) के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता भी समान परिस्थितियों में ऑपरेशन का हिस्सा थे। इसी भेदभाव से आहत होकर उन्होंने 25 जून 2025 को पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जो अब तक लंबित है।

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं का दावा अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में कोर्ट ने इस स्तर पर सीधे पदोन्नति का आदेश न देकर, प्रतिनिधित्व के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस महानिदेशक याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर पुलिस विनियम 70(क) के अनुसार कानून सम्मत एवं निष्पक्ष निर्णय लें। यह निर्णय दो माह के भीतर किया जाए। यदि याचिकाकर्ताओं का मामला उन 54 पदोन्नत पुलिसकर्मियों के समान पाया जाता है, तो उनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए।

हिमंता पहले संपत्ति की जांच कराएं,फिर केस करें : भूपेश

सरमा ने किया है 500 करोड़ का मानहानि-केस,12000 बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप

रायपुर,11 फरवरी 2026। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ 500 करोड़ का मानहानि केस किया है। इनके साथ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है। यह मामला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए '12,000 बीघा जमीन' के कथित आरोपों से जुड़ा है। दरअसल,मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि, भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझकर गलत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए। जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।

इसलिए उन्होंने अदालत में सिविल और क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है।

वहीं भूपेश बघेल ने पलटवार किया है, उनके मुताबिक हेमंत बिस्वा सरमा को पहले यह बताना चाहिए कि क्या 12,000 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है? गौरव गोगोई ने यही सवाल उठाया है। केस दर्ज करने के बजाय उन्हें एक समिति गठित करके संपत्ति की जांच करानी चाहिए थी।

9 फरवरी को शुरू हुई कानूनी कार्रवाई

हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, 9 फरवरी 2026 को भूपेश बघेल सहित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि, राजनीतिक असहमति अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक मंच से निराधार आरोप लगाना कानून के दायरे में आता है। सीएम सरमा का आरोप है कि, कांग्रेस नेताओं, खासकर भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जो पूरी तरह झूठे और तथ्यहीन हैं। इसी को लेकर उन्होंने सीधे कोर्ट का रुख किया।

असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम निलंबित,नकली दवाओं के माफिया के साथ वीडियो हुआ था वायरल

रायपुर,11 फरवरी 2026। सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संचालक ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वे नकली दवाओं से जुड़े दवा माफिया के साथ रेस्टोरेंट में बैठक कर रहे थे और उन्हें कार्रवाई की विभागीय फाइल दिखा रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद एनएसयूआई ने इस मामले में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी। संजय कुमार नेताम सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर रायपुर में पदस्थ हैं। रायपुर के टैन कैफे में बैठकर वे नकली दवाओं से जुड़े प्रकरण के मामले में दवा माफियाओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। आरोप है कि वह विभागीय कार्रवाई से जुड़े महत्वपूर्ण फाइल दवा माफियाओं को दिखा रहे थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद

एनएसयूआई ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। एनएसयूआई ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम को धरने के दौरान पांच लाख रुपए दिए थे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)